

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एस बी मध्यस्थता आवेदन संख्या 104/2022

अक्षय वर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री दिनेश कुमार वर्मा , आयु 36 वर्ष, निवासी जी-51 वैशाली नगर, आनासागर सर्कुलर रोड, अजमेर, मेसर्स वर्मा एंड कंपनी, जयपुर रोड, अजमेर के पार्टनर।

----आवेदक

बनाम

स्वर्गीय श्रीमती सीता देवी वर्मा पत्नी स्वर्गीय श्री भीम सिंह वर्मा , निवासी घी मंडी , अजमेर वर्तमान में 346, गायत्री नगर-ए दुर्गापुरा , रेलवे ब्रिज के पास, जयपुर अब उनके कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से दिवंगत हो चुकी हैं:-

- 1/1. श्रीमती शंकुन्तला वर्मा पत्नी श्री अतुल स्वर्गीय श्रीमती की कारेल पुत्री। सीता देवी वर्मा , 346, गायत्री नगर-ए दुर्गापुरा , रेलवे ब्रिज के पास, जयपुर।
- 1/2. स्वर्गीय श्री राजेंद्र वर्मा , निवासी 614, साकेत नगर, आनासागर सर्कुलर रोड, अजमेर अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से
- 1/2/1. श्रीमती रजनी वर्मा, स्वर्गीय राजेंद्र की पत्नी वर्मा , उम्र लगभग 60 वर्ष,

- 1/2/2. श्रीमती कीर्ति वर्मा पुत्री स्वर्गीय श्री राजेंद्र वर्मा , उम्र लगभग 32 वर्ष,
- 1/2/3. श्रीमती त्रिपाठी वर्मा पुत्री स्वर्गीय श्री राजेंद्र वर्मा , उम्र लगभग 30 वर्ष,
- 1/2/4. कुमारी गिनी वर्मा पुत्री स्वर्गीय श्री राजेंद्र वर्मा , उम्र लगभग 21 वर्ष, सभी निवासी 614, साकेत नगर, आनासागर सर्कुलर रोड, अजमेर।

-----प्रतिवादी/गैर-आवेदक।

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री आशीष किशोर सक्सेना एडवोकेट
श्री हर्षित मित्तल एडवोकेट।

प्रतिवादी के लिए : श्री मनोरंजन सिंह कनक एडवोकेट।

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्रीमान. मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

(वीसी के माध्यम से)

आदेश

प्रकाशनीय

घोषित तिथि : 25/04/2024

1. आवेदक ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे आगे '1996 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थता की

प्रक्रिया के माध्यम से विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए प्रदान किए गए अनुबंध के पक्षकारों के बीच कथित विवाद के मामले में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए यह आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क के अनुसार, मेसर्स वर्मा एंड कंपनी, 214, जयपुर रोड, अजमेर भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (जिसे आगे '1932 का अधिनियम' कहा जाएगा) के प्रावधानों के अंतर्गत एक पंजीकृत फर्म है। दो साझेदारों में से एक, दिनेश कुमार वर्मा, की मृत्यु के पश्चात्, उनके पुत्र अक्षय वर्मा को 24.12.2013 से साझेदार के रूप में शामिल किया गया और नई साझेदारी का गठन किया गया जो 24.12.2013 को सीता देवी वर्मा और अक्षय के बीच निष्पादित साझेदारी विलेख के माध्यम से अस्तित्व में आई। वर्मा द्वारा हस्ताक्षरित, जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं। साझेदारी विलेख की धारा-9 में यह प्रावधान है कि सभी विवादों का निपटारा 1996 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा।

3. 14.03.2022 को, भागीदारों में से एक सीता देवी वर्मा ने शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि फर्म के नाम के खातों को रोक दिया जाए/बंद कर दिया जाए और उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने दामाद अतुल करेल के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की है। बैंक के शाखा प्रबंधक ने फर्म के खातों को फ्रीज करने के

लिए सीता देवी वर्मा के पत्र के संबंध में अन्य भागीदार अक्षय वर्मा को सूचित किया। 21.03.2022 को, अक्षय वर्मा ने उत्तर दिया कि फर्म बैंक की बहुत पुरानी ग्राहक रही है, इसलिए, अन्य भागीदार सीता देवी वर्मा द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर कोई कार्रवाई या संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। इसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से 26.03.2022 को एक और पत्र भेजा गया जिसमें सीता देवी वर्मा द्वारा बैंक को भेजे गए पत्र पर कोई कार्रवाई शुरू न करने या संज्ञान न लेने का अनुरोध दोहराया गया। सीता देवी वर्मा ने पुनः दिनांक 21.04.2022 को बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र भेजकर मेसर्स वर्मा एंड कंपनी के नाम से फर्म का ओवरड्राफ्ट खाता पुनः चालू करने का अनुरोध किया।

यह भी कहा गया है कि अक्षय वर्मा ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि पक्षों के बीच गलतफहमी दूर हो गई है और इसलिए, ओवरड्राफ्ट खाते के संचालन के लिए सहमति दे दी गई है। आवेदन में यह भी कहा गया है कि सीता देवी वर्मा ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विपणन प्रभाग को संबोधित दिनांक 29.06.2022 के पत्र में कहा था कि वह 89 वर्ष की निरक्षर महिला हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी शकुंतला करेल का नामांकन साझेदारी के लिए भेजा था। इस बीच, सीता देवी वर्मा का 12.07.2022 को निधन हो गया।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 04.08.2022 को फर्म मेसर्स वर्मा एंड कंपनी, अक्षय वर्मा, मृतक सीता देवी वर्मा के कानूनी प्रतिनिधियों और मृतक राजेंद्र वर्मा के कानूनी प्रतिनिधियों को फर्म का पुनर्गठन करके फर्म के पक्ष में आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करने या ब्याज और अन्य खर्चों के साथ 1,75,33,186/- रुपये की बकाया राशि चुकाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा, ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

5. चूंकि आवेदक- अक्षय के बीच पहले ही विवाद उत्पन्न हो चुका था वर्मा और सीता देवी वर्मा (अब दिवंगत) के मामले में, आवेदक ने गैर-आवेदकों, यानी मृतक सीता देवी वर्मा के कानूनी प्रतिनिधियों से विवाद को सुलझाने का अनुरोध किया, लेकिन बार-बार अनुरोध के बावजूद, गैर-आवेदकों ने निपटान के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए, एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया गया है।

6. आवेदन पर जवाब दाखिल करके, मृतक प्रतिवादी सं.1/1-शकुंतला वर्मा की कानूनी प्रतिनिधि , मृतक भागीदार सीता देवी वर्मा की पुत्री , ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए आवेदन का विरोध किया और इसे गलत और पोषणीय नहीं बताया। जवाब में, यह कहा गया है कि वर्तमान में फर्म के भागीदारों के बीच किसी भी वित्तीय विवाद या किसी अन्य प्रकार के विवाद का मामला नहीं है क्योंकि भागीदारों में से एक की मृत्यु हो गई थी। सीता

देवी वर्मा के कानूनी प्रतिनिधियों पर भागीदार बनने के लिए दबाव डाला जा रहा है। चूंकि वे कानून के संचालन या पक्षों के कृत्य से भागीदार नहीं हैं, इसलिए विवाद, यदि कोई हो, को फर्म के भागीदारों के बीच का विवाद नहीं कहा जा सकता है। विवाद के मामले में मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में साझेदारी विलेख की शर्तों का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है क्योंकि साझेदारी स्वयं दो भागीदारों में से एक की मृत्यु के कारण भंग हो गई है। प्रतिवादी सं.1/1-शकुंतला वर्मा फर्म में भागीदार भी नहीं हैं, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी अनुबंध में प्रवेश करने या फर्म में भागीदार बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता , इसलिए, मध्यस्थता खंड वाले अनुबंध के पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है। आवेदक के पास प्रतिवादी संख्या 1/1-शकुंतला वर्मा के विरुद्ध कार्रवाई का कोई कारण नहीं है , जिनका साझेदारी फर्म के दिन-प्रतिदिन के संचालन से कोई संबंध नहीं है। जब किसी साझेदारी फर्म के दो भागीदारों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो फर्म कानून के तहत स्वतः ही भंग हो जाती है और कोई साझेदारी अस्तित्व में नहीं रहती है। आवेदक और मृतक सीता देवी वर्मा के बीच मौजूद साझेदारी विलेख में ऐसा कोई खंड नहीं था कि किसी एक भागीदार की मृत्यु होने पर, मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। फर्म में साझेदार के रूप में। इसलिए, मृतक सीता देवी वर्मा के कानूनी प्रतिनिधियों को साझेदारी फर्म

में स्वतः शामिल नहीं किया जा सकता, जैसा कि आवेदक और सीता देवी वर्मा के बीच सीता देवी वर्मा के जीवित रहते हुए था। आवेदक- अक्षय के बीच साझेदारी विलेख में मध्यस्थता खंड वर्मा और सीता देवी वर्मा के मामले में मृतक श्रीमती सीता देवी वर्मा के कानूनी प्रतिनिधि के विरुद्ध अब कोई प्रावधान नहीं लगाया जा सकता । उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 1/1-शकुंतला वर्मा , सीता देवी वर्मा की पुत्री, आवेदक अक्षय के साथ न तो साझेदार थी और न ही उसने कोई नई साझेदारी की है। वर्मा , न ही उनका भागीदार बनने का कोई इरादा है। आवेदक प्रतिवादी संख्या 1/1-शकुंतला वर्मा को एक साझेदारी फर्म में प्रवेश करने और आवासीय संपत्ति के समतुल्य बंधक के रूप में सुरक्षा को समाप्त करके बैंक बकाया राशि की वसूली को रोकने के लिए मजबूर कर रहा है। यह भी कहा गया है कि सीता देवी वर्मा ने न केवल अपने जीवित रहते हुए बैंक को सुरक्षा को समाप्त करने और देय राशि वसूलने के लिए अपनी सहमति दी, बल्कि बाद में प्रतिवादी संख्या 1/1- शकुंतला वर्मा ने भी इसी तरह की सहमति दी। सहमति में यह भी कहा गया है कि यदि अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होती है , तो उसे प्रतिवादी संख्या 1/1- शकुंतला को दिया जाए । वर्मा । ओवरड्राफ्ट सुविधा के कारण फर्म की देनदारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए सीता देवी वर्मा ने बैंक को ओवरड्राफ्ट सुविधा बंद करने के लिए लिखा।

7. आवेदक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एक भागीदार सीता देवी वर्मा की मृत्यु के बावजूद , फर्म में एक भागीदार आवेदक और मृतक भागीदार के बीच मौजूद विवाद, आवेदक और मृतक सीता देवी वर्मा के बीच साझेदारी विलेख में निहित मध्यस्थता खंड के मद्देनजर एक मध्यस्थता विवाद है। सीता देवी वर्मा की मृत्यु के बाद भी , फर्म के भागीदारों के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है क्योंकि मृतक भागीदार श्रीमती की कानूनी प्रतिनिधि सीता देवी वर्मा मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो बैंक द्वारा फर्म को दिए गए ऋण के खिलाफ एक सुरक्षित संपत्ति है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 29.06.2022 के संचार के माध्यम से, सीता देवी वर्मा ने मेसर्स वर्मा एंड कंपनी की डीलरशिप के संबंध में अपनी बेटी शकुंतला (प्रतिवादी संख्या 1/1) का नामांकन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भेजा था। ऐसी आकस्मिक स्थिति में फर्म का विघटन पक्षों के बीच अनुबंध के अधीन है और कानूनी प्रतिनिधियों के साथ साझेदारी में व्यवसाय जारी रखने का इरादा पक्षों के अनुबंध से प्राप्त किया जा सकता है। वह आगे यह भी प्रस्तुत करेंगे कि यह नियम कि साझेदारी किसी एक भागीदार की मृत्यु पर भंग हो जाएगी, पक्षों के बीच एक अनुबंध के अधीन है, जो व्यक्त या निहित हो सकता है। इसके विपरीत किसी भी समझौते के अभाव में, मृतक भागीदार का ख्याति सहित परिसंपत्तियों में

हिस्सा उसके/उसके कानूनी प्रतिनिधियों को हस्तांतरित हो जाता है, इसलिए, विवाद स्पष्ट रूप से मध्यस्थता योग्य है और आवेदक और मृतक भागीदार के कानूनी प्रतिनिधि के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है।

8. प्रति-विपक्ष में, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि मेसर्स वर्मा एंड कंपनी के नाम से साझेदारी फर्म में केवल दो साझेदार थे: आवेदक और मृतक सीता देवी वर्मा । हालाँकि आवेदक और मृतक सीता देवी वर्मा के बीच साझेदारी विलेख में एक मध्यस्थता खंड था जिसके अनुसार विवाद 1996 के अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थ को भेजा जाएगा, फिर भी दोनों साझेदारों में से किसी एक की मृत्यु होने पर, फर्म कानून के अनुसार स्वतः ही भंग हो जाती थी। सीता देवी वर्मा की मृत्यु से पहले , प्रतिवादी संख्या 1/1-शकुंतला वर्मा ने ऐसा नहीं किया था। था आवेदक-अक्षय को तत्कालीन फर्म में भागीदार के रूप में शामिल नहीं किया गया था , न ही उसके बाद आवेदक -अक्षय के बीच कोई नई साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया गया था। वर्मा और शकुंतला वर्मा , या मृतक सीता देवी वर्मा के किसी अन्य कानूनी प्रतिनिधि । पक्षों के बीच, यानी आवेदक और शकुंतला के बीच कोई समझौता नहीं है वर्मा , या मृतक सीता देवी वर्मा के अन्य कानूनी प्रतिनिधियों के साथ मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से अपने

विवाद को सुलझाने के लिए। आवेदक- अक्षय के बीच समझौता वर्मा और सीता देवी वर्मा के बीच मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से अपने विवाद को सुलझाने के लिए किया गया समझौता, सीता देवी वर्मा की मृत्यु के साथ साझेदारी फर्म के स्वतः विघटन के कारण स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गया। उक्त समझौते को मृतक सीता देवी वर्मा के कानूनी प्रतिनिधियों के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता । भले ही यह मान लिया जाए, हालाँकि स्वीकार नहीं किया गया है कि वर्तमान आवेदक अक्षय के बीच कोई विवाद था। वर्मा ने मृतक सीता देवी वर्मा के कानूनी प्रतिनिधियों के साथ , बैंक ऋण की वसूली के लिए सुरक्षित संपत्तियों के परिसमापन और सुरक्षित संपत्तियों पर संबंधित दावों के संबंध में और किसी समझौते के अभाव में, वर्तमान आवेदक और मृतक सीता देवी वर्मा के कानूनी प्रतिनिधियों के बीच विवाद को मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से संदर्भित करने के लिए , आवेदक के कहने पर मध्यस्थता कार्यवाही का कोई सहारा नहीं लिया जा सका। प्रतिवादियों के वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि भले ही यह मान लिया जाए कि सीता देवी वर्मा ने , जब वह जीवित थीं, 29.06.2022 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एक पत्र भेजा था जिसमें गैर-आवेदक प्रतिवादी संख्या 1/1 अर्थात शकुंतला को शामिल करने का इरादा व्यक्त किया था। वर्मा को साझेदारों में से एक मानते हुए भी, तथ्य यह है कि शकुंतला

सीता देवी वर्मा के जीवनकाल में वर्मा को कभी भी फर्म में साझेदार नहीं बनाया गया । आवेदक का यह मामला नहीं है कि सीता देवी वर्मा की मृत्यु के बाद, वर्तमान आवेदक- अक्षय के बीच कोई नई साझेदारी गठित की गई थी। वर्मा और शकुंतला वर्मा , मृतक सीता देवी वर्मा की पुत्री हैं । इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि यह विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं है ।

9. मध्यस्थ नियुक्त करके विवाद को संदर्भित करने के आवेदन का विरोध करते हुए, अनावेदकों ने मुख्यतः इस आधार पर पक्षों के बीच किसी समझौते के अस्तित्व से इनकार किया है कि किसी एक साझेदार की मृत्यु के बाद, साझेदारी फर्म भंग हो गई और पक्षों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है जिसमें यह प्रावधान हो कि पक्षों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, उसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। दूसरे, प्रतिवादियों ने आवेदक द्वारा उठाए गए विवाद की मध्यस्थता न किए जाने के संबंध में एक मुद्दा उठाया है । इसलिए, आवेदक के आवेदन को स्वीकार करने से पहले उपरोक्त दोनों मुद्दों पर निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

10. इससे पहले कि मैं मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर चर्चा करूं, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और विवाद की गैर- मध्यस्थता के पहलुओं पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के न्यायिक निर्णयों का उल्लेख करना उचित होगा।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक वृहद पीठ ने विद्या डोलिया एवं अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, (2021) 2 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 1 के मामले में, अपने समक्ष प्रस्तुत एक संदर्भ पर निर्णय देते हुए, अनुबंध के अस्तित्व और मध्यस्थता न होने के दोनों पहलुओं पर, संदर्भ चरण में न्यायिक समीक्षा के दायरे से संबंधित कानूनी स्थिति की विस्तृत जाँच की है। 1996 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, समय-समय पर किए गए संशोधनों और उपरोक्त पहलुओं से संबंधित पूर्व निर्णयों के अवलोकन के आधार पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कानूनी स्थिति की जाँच की:

“26. मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बारे में प्रश्न तब भी उठते हैं जब संदर्भ का विरोध करने वाला पक्ष मूल के स्थान पर एक नया अनुबंध करके अनुबंध के नवीकरण की दलील देता है या प्रदर्शन द्वारा अनुबंध के निर्वहन में संशोधित दायित्वों को स्वीकार करके या व्यक्त या निहित सहमति से सरल समाप्ति द्वारा 'समझौते और संतुष्टि' का तर्क देता है। इसी तरह की मुक्ति की दलील संदर्भ के लिए एक आवेदन का विरोध करते हुए इस आधार पर उठाई जा सकती है कि दावा लंबे समय से वर्जित और मृत है या कोई बकाया विवाद नहीं है क्योंकि पक्षों ने आंशिक प्रदर्शन को स्वीकार कर लिया है या दूसरे पक्ष को निराशा या अन्यथा के कारण, पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रदर्शन से मुक्त कर दिया है। तर्क यह है कि

एक बार मूल अनुबंध समाप्त हो जाने, त्याग दिए जाने, अस्वीकृत या प्रतिस्थापित हो जाने पर, अंतर्निहित/मूल अनुबंध में मध्यस्थता खंड इसके साथ नष्ट हो जाता है।

27.

31. हम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में संवैधानिक पीठ के फैसले के सिद्धांत से स्पष्ट रूप से बाध्य हैं कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत अदालत के अधिकार क्षेत्र का दायरा और दायरा समान है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन में विवादों या दावों को विस्तार से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है और संक्षेप में विवाद के विषय या व्यापक रूपरेखा का उल्लेख किया जा सकता है। हालांकि, जहां न्यायिक कार्यवाही शुरू की जाती है और लंबित होती है, दावों और विवादों का विशिष्ट विवरण आम तौर पर दलील दी जाती है और इसलिए, अदालत या न्यायिक प्राधिकारी को इन विवरणों का लाभ होता है। गैर-मध्यस्थता दावे और गैर- मध्यस्थता विषय वस्तु के बीच अंतर है । पूर्व मध्यस्थता समझौते के दायरे के कारण उत्पन्न हो सकता है और तब भी जब दावा मध्यस्थता के माध्यम से हल करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा, सुकन्या होल्डिंग्स (पी) लिमिटेड के फैसले को क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेट वाटर प्यूरिफिकेशन इंक. (2013) 1 एससीसी 641 में इस न्यायालय के बाद के फैसले के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

32.

71. मध्यस्थता को टालने के लिए जटिलता पर्याप्त नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के अधिदेश और मध्यस्थता अधिनियम के उद्देश्य एवं प्रयोजन तथा धारा 8 व 11 की अनिवार्य भाषा के अनुसार, पारस्परिक रूप से सहमत मध्यस्थता धाराओं को लागू किया जाना चाहिए। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 की भाषा अनिवार्य प्रकृति की है। मध्यस्थता को न्यायालयीय निर्णय के एक पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायसंगत विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए मध्यस्थता अधिनियम लागू किया गया है। सार्वजनिक नीति आर्थिक, वाणिज्यिक और दीवानी विवादों के समाधान और निपटारे के लिए मध्यस्थता को प्रोत्साहित और सुदृढ़ करना है। समय-समय पर किए गए संशोधनों ने इन मुद्दों का समाधान किया है और मध्यस्थता प्रक्रिया की अपर्याप्तताओं और खामियों को दूर किया है। मध्यस्थों सहित सभी हितधारकों का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मध्यस्थता न्यायालयीय निर्णय की तरह ही निष्पक्ष, न्यायसंगत और निष्पक्ष हो। पंचाट के बाद के चरण में न्यायालयों का यह भी कर्तव्य है कि वे धारा 34(2) (बी)(ii) के अंतर्गत, स्पष्टीकरण 1 और 2 के साथ, सीमित अधिकार क्षेत्र का चयनात्मक किन्तु प्रभावी ढंग से प्रयोग करें और लागू कानून की मूल नीति के साथ किसी भी टकराव की जाँच करें। इसके बाद हम 'दूसरी नज़र' सिद्धांत का उल्लेख करेंगे, जो

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के अधिदेश के अनुसार मध्यस्थता से संबंधित तीन विशिष्ट स्थितियों में लागू होता है।

72. हाल ही में, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने टेलस कम्युनिकेशंस इंकोर्पोरेशन बनाम अवराम वेलमैन, (2019) एस सी सी 19 मामले में यह स्वीकार करते हुए कि विवाद समाधान की एक विधि के रूप में मध्यस्थता को सार्वजनिक नीति के आधार पर लंबे समय तक "प्रकट शत्रुता" के साथ देखा गया था क्योंकि यह न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर देता है, यह टिप्पणी की कि नया कानून, 1991 का मध्यस्थता अधिनियम, एक बदलाव का प्रतीक है क्योंकि यह पक्षों को वाणिज्यिक और अन्य मामलों में मध्यस्थता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। पक्ष की स्वायत्तता को उच्च स्थान पर रखते हुए, अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि एक वैध मध्यस्थता समझौते के पक्षकारों को विवाद समाधान के सहमतिपूर्ण और सहमत तरीके का पालन करना चाहिए। न्यायालयों को, विशेष रूप से वाणिज्यिक परिस्थितियों में, अदालती कार्यवाही को स्थगित करके मध्यस्थता समझौतों के प्रति उचित सम्मान दिखाना चाहिए, जब तक कि विधायी भाषा इसके विपरीत न हो। पक्ष की स्वायत्तता का सिद्धांत सीमित न्यायालयी हस्तक्षेप के सिद्धांत के साथ-साथ चलता है, यह आधुनिक मध्यस्थता कानून का मूलभूत सिद्धांत है। बिना बातचीत वाले "इसे ले लो या छोड़ दो" अनुबंधों में पक्षकार की स्वायत्तता कमजोर होती है और

इसलिए, विधायिका कानूनों के ज़रिए उपभोक्ताओं जैसे सबसे कमज़ोर और असुरक्षित अनुबंधकारी पक्षों की रक्षा कर सकती है। बातचीत वाले समझौतों या व्यावसायिक परिस्थितियों में मध्यस्थता खंड वाले आसंजन अनुबंधों में भी ऐसा नहीं है। वाणिज्यिक और नागरिक मध्यस्थता के गुणों को मान्यता और स्वीकृति मिली है और अदालतें भी मध्यस्थता के उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं।

73

76. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, हम यह निर्धारित करने के लिए एक चार-स्तरीय परीक्षण प्रस्तुत करना चाहेंगे कि मध्यस्थता समझौते में विवाद का विषय कब मध्यस्थता योग्य नहीं है :

76.1 (1) जब कार्रवाई का कारण और विवाद की विषय वस्तु रेम में कार्रवाई से संबंधित होती है, जो रेम में अधिकारों से उत्पन्न अधीनस्थ व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित नहीं होती है।

76.2 (2) जब कार्रवाई का कारण और विवाद की विषय-वस्तु तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करती है ; सर्वव्यापी प्रभाव; केंद्रीकृत न्यायनिर्णयन की आवश्यकता होगी, और पारस्परिक न्यायनिर्णयन उचित और लागू करने योग्य नहीं होगा।

76.3 (3) जब कार्रवाई का कारण और विवाद की विषय-वस्तु राज्य के अविभाज्य संप्रभु और सार्वजनिक हित कार्यों से संबंधित हो और इसलिए पारस्परिक न्यायनिर्णयन अप्रवर्तनीय होगा।

76.4 (4) जब विवाद का विषय-वस्तु स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा अनिवार्य कानून(नों) के अनुसार गैर-मध्यस्थता योग्य हो।

76.5 ये परीक्षण निर्विवाद रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं; ये एक-दूसरे से जुड़े हुए और एक-दूसरे से ओवरलैप होते हैं, हालाँकि जब इन्हें समग्र और व्यावहारिक रूप से लागू किया जाता है, तो ये निश्चित रूप से यह निर्धारित करने और सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि भारत में कानून के अनुसार, कोई विवाद या विषय-वस्तु मध्यस्थता योग्य नहीं है। केवल तभी जब उत्तर सकारात्मक हो, तभी विवाद की विषय-वस्तु मध्यस्थता योग्य नहीं होगी।

76.6. हालाँकि, उपरोक्त सिद्धांतों को सावधानी और सतर्कता के साथ लागू किया जाना चाहिए जैसा कि ओलिंपस सुपरस्ट्रक्चर्स (पी) लिमिटेड में देखा गया है: (एससीसी पृष्ठ 669, पैरा 35)

"35...वहाँ कुछ विवादों का उल्लेख किया गया है जैसे सार्वजनिक प्रकृति के आपराधिक अपराध, अवैध समझौतों से उत्पन्न विवाद और स्थिति से संबंधित विवाद, जैसे तलाक, जिन्हें मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता। हालाँकि, यह माना गया है कि यदि

किसी आपराधिक मामले से संबंधित वसा के संबंध में, शारीरिक चोट कहें, यदि व्यक्तिगत चोट के लिए हर्जाना पाने का अधिकार है, तो ऐसे विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है (केइर बनाम लीमन)। इसी प्रकार, यह माना गया है कि एक पति और पत्नी मध्यस्थता को उन शर्तों का उल्लेख कर सकते हैं जिन पर वे अलग होंगे, क्योंकि वे उस मामले पर आपस में एक वैध समझौता कर सकते हैं (सोइलक्स बनाम हर्बस्ट , विल्सन बनाम विल्सन और काहिल बनाम काहिल)।"

77. गैर मध्यस्थता का निर्धारण करने के लिए उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि दिवालियापन या अंतर-कंपनी विवादों को एक केंद्रीकृत मंच द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए, चाहे वह न्यायालय हो या विशेष मंच, जो अधिक कुशल होगा और पूरे मामले को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निपटाने के लिए पूर्ण क्षेत्राधिकार रखता होगा। वे भी खिलाफ कार्रवाई हैं इसी तरह, पेटेंट का अनुदान और जारी करना और ट्रेडमार्क का पंजीकरण संप्रभु या सरकारी कार्यों के अंतर्गत आने वाले अनन्य मामले हैं और उनका व्यापक प्रभाव होता है। इस तरह के अनुदान एकाधिकार अधिकार प्रदान करते हैं। वे गैर मध्यस्थता योग्य हैं। आपराधिक मामले भी मध्यस्थता योग्य नहीं हैं क्योंकि वे राज्य के संप्रभु कार्यों से संबंधित हैं। इसके अलावा, आपराधिक कानून का उल्लंघन राज्य के खिलाफ अपराध है, न कि केवल पीड़ित के खिलाफ। विवाह विच्छेद, वैवाहिक अधिकारों की बहाली आदि से

संबंधित वैवाहिक विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं हैं क्योंकि वे संप्रभु कार्यों के दायरे में आते हैं और उनका कोई वाणिज्यिक और आर्थिक मूल्य नहीं है प्रोबेट, वसीयतनामा संबंधी मामले आदि से संबंधित मामले, रेम में की जाने वाली कार्रवाई हैं तथा ये व्यापक रूप से विश्व के लिए एक घोषणा हैं, इसलिए इन पर मध्यस्थता नहीं की जा सकती।

78.

82. मध्यस्थता न होने का मुद्दा तीन चरणों में उठाया जा सकता है। पहला, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत संदर्भ के लिए या लंबित न्यायिक कार्यवाही पर रोक लगाने और धारा 8 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन पर न्यायालय के समक्ष; दूसरा, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष; या तीसरा, निर्णय या उसके प्रवर्तन को चुनौती देने के चरण में न्यायालय के समक्ष। इसलिए, प्रश्न यह है कि - 'मध्यस्थता न होने का निर्णय कौन करता है?' और, विशेष रूप से, प्रथम दृष्टया चरण, अर्थात् रेफरल चरण में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र।

83.

84. मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत, अस्तित्व, वैधता, क्षेत्राधिकार के साथ-साथ क्या विषय-वस्तु मध्यस्थता योग्य है, से संबंधित गैर- मध्यस्थता संबंधी मुद्दों को निपटाने और उन पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र, समाप्ति, नवप्रवर्तन, निराशा और तथ्यों पर विवाद होने पर 'समझौते

और संतुष्टि' के मामले में संभावित अपवाद के साथ, न्यायालयों द्वारा पहले या संदर्भ चरण में निर्धारित और तय किया जाता था। सिद्धांत यह है कि न्यायालय को एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट होना चाहिए और यह कि विवाद मध्यस्थता समझौते की विषय-वस्तु के संबंध में उत्पन्न हुए हैं। हालाँकि, इस स्तर पर न्यायालय विवादों के गुण-दोष या स्थायित्व से चिंतित नहीं होगा। अवरोधक युक्तियों को नियंत्रित करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, संदर्भ चरण में गैर- मध्यस्थता संबंधी मुद्दों का न्यायनिर्णयन और अंतिम निर्णय अनिवार्य रूप से न्यायालयों में कार्यवाही को वर्षों तक रोक देगा, पटरी से उतार देगा और विफल कर देगा।

85.

103. संदर्भ चरण में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे पर, शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड बनाम अक्ष में यह देखा गया था ऑप्टिफाइबर लिमिटेड एवं अन्य (2005) 7 एससीसी 234 में कहा गया है कि मध्यस्थता समझौते की समीक्षा का सही तरीका प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष तक सीमित होगा कि ऐसा मध्यस्थता समझौता मौजूद है जो शून्य और अमान्य, निष्क्रिय या निष्पादित करने योग्य नहीं है। मध्यस्थता समझौते की अदालतों की समीक्षा को प्रथम दृष्टया मानक तक सीमित रखने के पीछे मुख्य तर्क सक्षमता का सिद्धांत है। इसके अलावा, यदि अदालतों को मध्यस्थता समझौते की पूरी

तरह से जांच करने का अधिकार दिया जाना है तो मध्यस्थता कार्यवाही को तब तक रोकना होगा जब तक कि मामले को देखने वाला न्यायालय मध्यस्थता समझौते पर कोई निर्णय न दे दे। यदि अदालतों का निष्कर्ष अंतिम और निर्णायक होगा, तो यह स्पष्ट है कि जब तक ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया जाता, मध्यस्थता कार्यवाही स्थगित रखनी होगी। यह स्पष्ट रूप से मध्यस्थता अधिनियम के मूल सिद्धांत और मूल भावना को विफल कर देगा, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्राधिकारियों के अपरिहार्य हस्तक्षेप के बिना शीघ्र मध्यस्थता को सक्षम बनाना है। परिणामस्वरूप, संदर्भ चरण में अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण यह है कि क्या यह 'स्पष्ट रूप से तर्क योग्य' है कि मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में है। निर्णय में इस तथ्य पर बल दिया गया कि मध्यस्थों के पक्ष में प्राथमिकता का नियम मध्यस्थता प्रक्रिया के अंत में मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता की समीक्षा करने की अदालतों की शक्ति द्वारा प्रति-संतुलित होता है। इसे स्पष्ट किया गया: (शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड, सुप्रा)।

“74.....भले ही न्यायालय यह मानता हो कि मध्यस्थता समझौता दोषपूर्ण नहीं है या यह अवैध, निष्क्रिय या लागू न करने योग्य नहीं है, विशुद्ध रूप से प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण के आधार पर, मध्यस्थ को इस मुद्दे पर पूरी तरह से विचार करने और उस पर अंतिम निर्णय देने से कोई नहीं रोकता है...।

75.... न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया यह मान लेने के बाद भी कि धारा 45 में उल्लिखित कारकों के कारण मध्यस्थता समझौता दोषपूर्ण नहीं है, और मध्यस्थ पूर्ण सुनवाई के बाद यह मान लेता है कि मध्यस्थता समझौते में कोई दोषपूर्ण कारक नहीं है और पंचाट सुनाता है, ऐसे पंचाट को धारा 48(1)(क) के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। पंचाट को तब रद्द कर दिया जाएगा यदि वह पक्ष, जिसके विरुद्ध यह आदेश दिया गया है, न्यायालय को अन्य बातों के साथ-साथ इस बात से संतुष्ट कर दे कि समझौता उस कानून के अंतर्गत वैध नहीं था जिसके अधीन पक्षकारों ने इसे किया था या उस देश के कानून के अंतर्गत जहां पंचाट दिया गया था। दो मूलभूत आवश्यकताएं, अर्थात्, पूर्व-संदर्भ चरण में शीघ्रता, और पूर्ण सुनवाई के बाद पंचाट को चुनौती देने का उचित अवसर, धारा 45 की व्याख्या द्वारा पूरी तरह संतुष्ट होंगी क्योंकि यह न्यायालय को प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करने में सक्षम बनाती है।

105. यदि मध्यस्थता शुरू होने के बाद भी कार्यवाही न्यायालय में लंबित रहती है, तो अधिनियम का उद्देश्य विफल हो जाएगा। यही कारण है कि मैं इस विचार से सहमत हूँ कि धारा 45 द्वारा परिकल्पित पूर्व-संदर्भ चरण में, न्यायालय को संदर्भ बनाने के लिए केवल प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, तथा पक्षों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण

के समक्ष या पंचाट-पश्चात चरण में न्यायालय के समक्ष पूर्ण सुनवाई के लिए छोड़ देना चाहिए।”

104.

132. रेफरल चरण में न्यायालय मंत्रिस्तरीय कार्य नहीं करते। वे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के अनुसार आपत्तियों का निपटारा करते समय न्यायिक कार्य करते हैं। धारा 8 न्यायालयों को निर्देश देती है कि यदि लाया गया मामला मध्यस्थता समझौते का विषय है, तो वे पक्षों को मध्यस्थता के लिए रेफर करें, जब तक कि उन्हें यह न लगे कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है। गुजरात राज्य, (2013) 4 एससीसी 301, में इस न्यायालय ने टिप्पणी की थी: (एससीसी पृष्ठ 320, पैरा 48)

“48. '27... प्रथम दृष्टया मामले का अर्थ पूरी तरह सिद्ध मामला नहीं है, बल्कि ऐसा मामला है जिसे स्थापित कहा जा सकता है यदि मामले के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास किया जाए। यह निर्धारित करते समय कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, प्रासंगिक विचार यह है कि क्या प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विचाराधीन निष्कर्ष पर पहुँचना संभव था, न कि यह कि क्या उस साक्ष्य के आधार पर केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता था।”

133. धारा 8 के संदर्भ में प्रथम दृष्टया मामले को पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मामले के गुण-दोष से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जिसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष स्थापित किया

जाना है। यह मुकदमे के विषय-वस्तु के प्रथम दृष्टया एक वैध मध्यस्थता समझौते के तहत मध्यस्थता योग्य होने तक सीमित है। प्रथम दृष्टया मामले का अर्थ है कि इन पहलुओं पर दावे वास्तविक हैं। पृथक्करण और क्षमता-क्षमता के सिद्धांतों और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के साथ पढ़ने पर, रेफरल न्यायालय बिना किसी बाधा के पक्षकारों को अनुपालन के लिए बाध्य करेगा, जब तक कि इसके विपरीत उचित और पर्याप्त कारण न हों।

134. प्रथम दृष्टया परीक्षण पूर्ण समीक्षा नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से और पूर्व दृष्टया अस्तित्वहीन और अमान्य मध्यस्थता समझौतों और मध्यस्थता-योग्य न होने वाले विवादों को छाँटने के लिए एक प्राथमिक समीक्षा है। संदर्भ चरण में प्रथम दृष्टया समीक्षा का उद्देश्य उन सीधे-सादे मामलों में, जहाँ खारिजी स्पष्ट और पारदर्शी है, मृत लकड़ी को काटना और पार्श्व शाखाओं को छाँटना है और जहाँ तथ्यों और कानून के आधार पर मुकदमेबाजी को पहले चरण पर ही रोक देना चाहिए। केवल तभी जब न्यायालय को यह विश्वास हो कि कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या विवाद/विषय-वस्तु मध्यस्थता-योग्य नहीं है, धारा 8 के तहत आवेदन खारिज किया जाएगा। इस स्तर पर, न्यायालय को उलझाव में नहीं पड़ना चाहिए और तथ्यों के विवादास्पद प्रश्नों पर निर्णय लेना चाहिए। रेफरल कार्यवाही प्रारंभिक और संक्षिप्त होती है, न कि एक छोटा मुकदमा। यह अनिवार्य रूप

से न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार क्षेत्र की प्रकृति को दर्शाता है और इस संदर्भ में, शिन-एत्सु केमिकल कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) में "स्पष्ट रूप से तर्क-योग्य" मामले में न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। विमल मामले में भी इसी न्यायालय ने इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। किशोर शाह बनाम जयेश दिनेश शाह (2016) 8 एससीसी 788 जिसमें पूर्व-मध्यस्थता चरण में लागू परीक्षण यह था कि क्या मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के लिए एक "अच्छा तर्क योग्य मामला" है।

135.

139. हम बहुत ज़्यादा निर्देशात्मक नहीं होना चाहेंगे, हालाँकि हम यह मानते हैं कि न्यायालय वैध कारणों से, सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी रोकने के लिए, न्यायिक विवेक का प्रयोग करके एक गहन लेकिन संक्षिप्त प्रथम दृष्टया समीक्षा कर सकता है, जबकि उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह मध्यस्थता प्रक्रिया में सहायता के लिए है, न कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने के लिए। रेफरल चरण में विस्तृत, पूर्ण समीक्षा या लंबी समीक्षा करने से बाधा उत्पन्न होगी और देरी होगी, जिससे विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अखंडता और प्रभावकारिता कमज़ोर होगी। इसके विपरीत, यदि न्यायालय हस्तक्षेप करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है, तो यह मध्यस्थता और न्यायालय दोनों की प्रभावशीलता को कमज़ोर

कर सकता है। कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ प्रथम दृष्टया जाँच के लिए गहन विचार की आवश्यकता हो सकती है। न्यायालय की चुनौती यह है कि वह सही मात्रा और संदर्भ का पता लगाए जब वह प्रथम दृष्टया मामले की जाँच करे या संयम बरते। कानूनी व्यवस्था के लिए रेफरल चरण में मध्यस्थता में बाधा डालने वाली युक्तियों से बचने और जब मामला स्पष्ट रूप से मध्यस्थता योग्य न हो, तब पक्षों को मध्यस्थता के लिए मजबूर होने से बचाने के बीच एक सही संतुलन की आवश्यकता होती है ।

140.

143. अब हम मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 का परीक्षण करेंगे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उप-धारा (6-ए) को 2016 के अधिनियम 3 द्वारा 23-10-2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव से सम्मिलित किया गया था और 2019 के अधिनियम 33 द्वारा हटा दिया गया था। धारा 11 (6) के अनुसार न्यायालय को किसी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर एक मध्यस्थ नियुक्त करना आवश्यक है। धारा 11 की धारा (6-ए) में प्रावधान है कि न्यायालय, उपधारा (4), (5) या (6) के अंतर्गत नियुक्ति के चरण में, स्वयं को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जाँच तक ही सीमित रखेगा। उप-धारा (6-ए) को 2019 के अधिनियम 33 द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट , दिनांक 30-07-2017 के अनुसार, संस्थागत

मध्यस्थता की एक नई व्यवस्था की शुरुआत के मद्देनजर यह चूक हुई है, जिसमें चूक की सिफारिश करने का कारण इस प्रकार दर्ज किया गया है:

"इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि 2019 के संशोधन अधिनियम के बाद, धारा 11 (6-ए) को हटा दिया गया है क्योंकि मध्यस्थों की नियुक्ति संस्थागत रूप से की जानी है, ऐसे में पुरानी वैधानिक व्यवस्था के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को अब मध्यस्थों की नियुक्ति करने और परिणामस्वरूप यह निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है कि मध्यस्थता समझौता मौजूद है या नहीं।"

144. जैसा कि पहले देखा गया है, एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (2005) 8 एससीसी 618 स्पष्ट करता है और मानता है कि धारा 8 और 11 प्रकृति में पूरक हैं क्योंकि दोनों मध्यस्थता के संदर्भ से संबंधित हैं। धारा 8 तब लागू होती है जब न्यायिक कार्यवाही लंबित हो और न्यायिक कार्यवाही पर रोक लगाने और मध्यस्थता के संदर्भ के लिए आवेदन दायर किया जाता है। 2016 के अधिनियम 3 के तहत धारा 8 में संशोधन को हटाया नहीं गया है। धारा 11 उस स्थिति को कवर करती है, जहां पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रद्युत देब बर्मन , (2019) 8 एससीसी 714 हमारी विनम्र राय में, सही ढंग से मानता है कि पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (सुप्रा) को विधायी रूप से खारिज कर

दिया गया है और इसलिए यह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 में उपधारा (6-ए) के लोप के बाद भी लागू नहीं होगा। मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) ने उप-धारा (6-ए) के संदर्भ में धारा 11 में संशोधन के उद्देश्य, प्रयोजन और इतिहास पर विस्तार से प्रकाश डाला है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि मूल रूप से अधिनियमित यह धारा, मध्यस्थता कानून के यूएनसीआईटीआरएल मॉडल के अनुच्छेद 11 के अनुरूप थी, जिस पर मध्यस्थता अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था और उसे अधिनियमित किया गया था। धारा 11 की विधायी योजना, विभिन्न व्याख्याओं और विधि आयोग की रिपोर्टों का हवाला देते हुए, यह माना गया है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 की हटाई गई उप-धारा (6-ए) पहले चरण, अर्थात् मध्यस्थता-पूर्व चरण में, न्यायालयों पर लागू होती रहेगी और अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती रहेगी।

145. 2019 के अधिनियम 33 द्वारा उप-धारा (6-ए) का लोप विशिष्ट उद्देश्य और प्रयोजन के साथ किया गया था और यह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 में उप-धारा (12), (13) और (14) के प्रतिस्थापन से संबंधित है, जो उप-धारा (3ए) के अनुसार यह निर्धारित करता है कि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय को मध्यस्थता संस्थानों को नामित करने की शक्ति होगी, जिन्हें परिषद द्वारा धारा 43-आई के तहत वर्गीकृत किया गया है, बशर्ते कि जहां एक वर्गीकृत

मध्यस्थता संस्थान उपलब्ध नहीं है, संबंधित उच्च न्यायालय कार्य का निर्वहन करने के लिए मध्यस्थों का एक पैनल बनाए रखेगा और उसके बाद उच्च न्यायालय मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए एक मध्यस्थ संस्थान का कर्तव्य निभाएगा। इसलिए, यह मानना गलत होगा कि धारा 11 में उप-धारा (6-ए) के लोप के बाद पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (सुप्रा) में अनुपात लागू हो जाएगा।

146. अब हम इस प्रश्न की जाँच करेंगे कि क्या धारा 11 में 'अस्तित्व' शब्द केवल अनुबंध निर्माण (चाहे कोई मध्यस्थता समझौता हो) को संदर्भित करता है और प्रवर्तन (वैधता) के प्रश्न को बाहर करता है और इसलिए यह रेफरल चरण में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है। न्यायशास्त्र और पाठ्यवाद के आधार पर मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और मध्यस्थता समझौते की वैधता के बीच अंतर करना संभव है। इस तरह की व्याख्या "अस्तित्व" शब्द के स्पष्ट अर्थ से समर्थन प्राप्त कर सकती है। हालाँकि, न्यायशास्त्र और संदर्भवाद के आधार पर, यह मानना भी समान रूप से संभव है कि यदि कोई समझौता प्रवर्तनीय और बाध्यकारी नहीं है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व एक वैध समझौते की पूर्वकल्पना करता है जिसे न्यायालय द्वारा पक्षों को मध्यस्थता के अधीन करके लागू किया जाएगा। विधिसम्मत और स्पष्ट अर्थ वाली व्याख्या, परिभाषा खंड सहित संदर्भगत पृष्ठभूमि के विपरीत होगी और

इसके अप्रिय परिणाम होंगे। 'अस्तित्व' की एक उचित और न्यायसंगत व्याख्या के लिए संदर्भ, उद्देश्य और एक बाध्यकारी तथा प्रवर्तनीय मध्यस्थता समझौते के लिए लागू प्रासंगिक कानूनी मानदंडों को समझना आवश्यक है। लिखित रूप में प्रमाणित समझौते का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि पक्षों को शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य न किया जा सके। कोई भी पक्ष किसी अप्रवर्तनीय दस्तावेज़ के आधार पर मुकदमा नहीं कर सकता और अधिकारों का दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार, यह मानने के अच्छे कारण हैं कि मध्यस्थता समझौता तभी अस्तित्व में रहता है जब वह वैध और कानूनी हो। एक शून्य और अप्रवर्तनीय समझौता किसी भी कार्य के लिए कोई समझौता नहीं है। अस्तित्व मध्यस्थता समझौते का अर्थ है एक मध्यस्थता समझौता जो मध्यस्थता अधिनियम और अनुबंध अधिनियम दोनों की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और संतुष्ट करता है और जब यह कानून में लागू करने योग्य होता है।

147. हम आगे विस्तार से बताएंगे और कारण भी बताएंगे:

147.1. गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम कोस्टल मरीन कंस्ट्रक्शन्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (2019) 9 एससीसी 209 में, इस न्यायालय ने मध्यस्थता खंड के साथ एक अंतर्निहित अनुबंध में स्टॉप शुल्क के प्रश्न की जांच की थी और इस संदर्भ में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(2) के पहले और दूसरे भाग के बीच अंतर किया था, यद्यपि

मध्यस्थता समझौते के 'अस्तित्व' और 'वैधता' के संदर्भ में ऊपर की गई और उद्धृत टिप्पणियां उपयुक्त और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, हम इसके पैरा 29 को पुनः प्रस्तुत करके इसे दोहराएंगे: (एससीसी पृष्ठ 238)

“29. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन्स कंपनी लिमिटेड (2018) 17 एससीसी 607 में यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि विशेष रूप से विचाराधीन एक मध्यस्थता खंड था जो केवल तभी सक्रिय होगा जब कोई बीमाकर्ता दायित्व स्वीकार करता है या स्वीकार करता है। चूंकि तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि बीमाकर्ता ने दावे को अस्वीकार कर दिया, हालांकि एक मध्यस्थता खंड "मौजूद" था, इसलिए बोलने के लिए, पॉलिसी में, यह कानून में मौजूद नहीं होगा, जैसा कि उस फैसले में आयोजित किया गया था, जब एक महत्वपूर्ण तथ्य पेश किया जाता है, अर्थात्, बीमाकर्ता ने दायित्व स्वीकार नहीं किया है या स्वीकार नहीं किया है। इसी तरह, वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि उप-अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड कानून के मामले के रूप में "मौजूद" नहीं होगा जब तक कि उप-अनुबंध विधिवत रूप से मुहर नहीं लगाता है, जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर आयोजित किया गया है। तर्क यह है कि धारा 11 (6-ए) "अस्तित्व" से संबंधित है, धारा 8, धारा 16 और धारा 45 के विपरीत, मध्यस्थता समझौते की "वैधता" का उत्तर इस न्यायालय द्वारा

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) मामले में "अस्तित्व" शब्द की समझ से मिलता है, जैसा कि हमने आगे बताया है।

अस्तित्व और वैधता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यदि मध्यस्थता समझौता अवैध है या अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो वह अस्तित्व में नहीं है। अमान्य समझौता कोई समझौता नहीं है।

147.2. संदर्भ चरण में न्यायालय न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है। 'परीक्षण', आम बोलचाल में एक सामान्य अभिव्यक्ति के रूप में, कुछ खोजने के लिए किसी चीज़ को ध्यान से देखने या विचार करने के एक कार्य को संदर्भित करता है (कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार)। इसके लिए व्यक्ति को बारीकी से निरीक्षण करने, स्थिति का परीक्षण करने या सावधानीपूर्वक पूछताछ करने की आवश्यकता होती है (मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार)। न्यायालय के लिए यह मानना और कहना अजीब होगा कि मध्यस्थता समझौता मौजूद है, हालांकि पूर्व दृष्ट्या और स्पष्ट रूप से मध्यस्थता समझौता कानून में अमान्य है और विचाराधीन विवाद गैर-मध्यस्थता योग्य है। न्यायालय शक्तिहीन नहीं है और अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य नहीं करेगा, यदि यह संदर्भ के लिए आवेदन को खारिज करता है, जब मध्यस्थता खंड स्वीकार्य रूप से या बिना किसी संदेह के नाबालिग, पागल या एकमात्र दावे के साथ वसीयत की प्रोबेट की मांग करता है।

147.3. अधिकांश विद्वान और न्यायविद इस बात को स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व और वैधता एक ही हैं। यहाँ तक कि स्टारवोस भी ब्रेकोउलाकिस स्वीकार करते हैं कि मूल और औपचारिक वैधता के संदर्भ में वैधता, अनुबंध का प्रश्न है और इसलिए न्यायालय को इसकी जांच करनी चाहिए।

147.4. रेफरल चरण में गैर- मध्यस्थता पहलुओं पर न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया समीक्षा को स्वीकार करते हैं और इसकी आवश्यकता रखते हैं ।

147.5. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 पूरक प्रावधान हैं जैसा कि पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (सुप्रा) में माना गया था। दोनों प्रावधानों के पीछे उद्देश्य और प्रयोजन पक्षों को उनके संविदात्मक समझ का पालन करने के लिए बाध्य और मजबूर करना समान है। ऐसा होने के कारण, दोनों प्रावधानों को समान मानक निर्धारित करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि अलग और पृथक पैरामीटर निर्धारित करने के रूप में। धारा 11 यह निर्धारित करने के लिए अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा का कोई मानक निर्धारित नहीं करती है कि क्या कोई मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में है। धारा 8 में कहा गया है कि संदर्भ के स्तर पर न्यायिक समीक्षा प्रथम दृष्टया है और अंतिम नहीं है। प्रथम दृष्टया मानक समान रूप से तब लागू होता है जब मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11

के तहत अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जाता है।

147.6. वैधता सहित अस्तित्व की प्रथम दृष्टया न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग उचित है क्योंकि न्यायालय वह पहला मंच है जो रेफरल के अनुरोध की जाँच और निर्णय लेता है। पूर्णतः "हाथ न लगाने" का दृष्टिकोण प्रतिकूल होगा और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता को नुकसान पहुँचाएगा। सीमित, फिर भी प्रभावी हस्तक्षेप स्वीकार्य है क्योंकि यह मध्यस्थता में बाधा नहीं डालता बल्कि उसे प्रभावी बनाता है।

147.7. सीमित प्रथम दृष्टया समीक्षा का प्रयोग किसी भी तरह से सक्षमता- सक्षमता और पृथक्करण के सिद्धांत में हस्तक्षेप नहीं करता है, जिससे मध्यस्थता कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो, बल्कि यह सुनिश्चित होता है कि परेशान करने वाले और तुच्छ मामले प्रारंभिक चरण में ही समाप्त हो जाएं।

147.8. मध्यस्थता समझौते की वैधता के संबंध में न्यायिक समीक्षा की प्रथम दृष्टया शक्ति का प्रयोग करने से लागत में बचत होगी और आपत्ति करने वाले पक्षों को होने वाले उत्पीड़न पर रोक लगेगी, जब मध्यस्थता न होने की दलील को स्वीकार न करने का स्पष्ट रूप से कोई औचित्य और उचित कारण न हो। सुब्रत रॉय सहारा बनाम भारत संघ, (2014) 8 एससीसी 470 में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की है: (एससीसी पृष्ठ 642, पैरा 191)

“191. भारतीय न्याय व्यवस्था तुच्छ मुकदमों से बुरी तरह ग्रस्त है। मुकदमों को निरर्थक और बिना सोचे-समझे दावों के प्रति उनके बाध्यकारी जुनून से रोकने के लिए तरीके और साधन विकसित करने की आवश्यकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में, हर गैर-जिम्मेदार और निरर्थक दावे के दूसरी तरफ एक निर्दोष पीड़ित होता है। वह लंबे समय तक घबराहट और बेचैनी के दौर से गुजरता है, जबकि मुकदमा उसकी ओर से बिना किसी गलती के लंबित रहता है। वह अपनी बचत (या अपने उधार) से मुकदमे का खर्च उठाता है, इस चिंता में कि दूसरा पक्ष उसे बिना उसकी किसी गलती के भी हरा सकता है। वह वकीलों को जानकारी देने और उन्हें अपने दावे के लिए तैयार करने में अपना अमूल्य समय लगाता है। जो समय उसे काम पर या अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए था, वह उसकी किसी गलती के बिना ही बर्बाद हो जाता है। क्या एक मुकदमेबाज को उसकी उस गलती के लिए मुआवजा नहीं मिलना चाहिए जो उसने बिना किसी गलती के खो दी है? विधायिका को सुझाव है कि जो मुकदमा सफल हुआ है, उसे हारने वाले द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। विधायिका को सुझाव है एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए कि जो कोई भी मुकदमा शुरू करता है और उसे जारी रखता है, उसे बेवजह उसकी कीमत चुकानी पड़े। यह सुझाव दिया जाता है कि विधायिका को एक

"अनिवार्य लागत संहिता" लागू करने पर विचार करना चाहिए।

147.9 इयूरो में भी फेलगुएरा , एसए बनाम गंगावरम पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एससीसी 729, कुरियन जोसेफ, जे. ने पैरा 52 में धारा 7(5) का उल्लेख किया था और उसके बाद पैरा 53 में एमआर इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स (पी) लिमिटेड बनाम सोम में इस न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख किया था। दत्त बिल्डर्स लिमिटेड, (2009) 7 एससीसी 696, यह देखने के लिए कि उक्त मामले में विश्लेषण इस अंतिम निष्कर्ष का समर्थन करता है कि उक्त मामले में समझौता ज्ञापन में मध्यस्थता खंड शामिल नहीं था। इसके बाद, विशेष रूप से एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (सुप्रा) और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोधारा का संदर्भ दिया गया। पॉलीफैब (पी) लिमिटेड (2009) 1 एससीसी 267 में यह टिप्पणी की गई कि मध्यस्थता-पूर्व चरण में न्यायालय के हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए विधायी नीति आवश्यक है और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (6) का यही उद्देश्य था। इयूरो में अनुच्छेद 48 फेलगुएरा , एसए (सुप्रा) स्पष्ट रूप से कहता है कि समाधान मध्यस्थता समझौते में मौजूद होना चाहिए, और यह देखना अदालत का काम है कि क्या समझौते में कोई ऐसा खंड है जो पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों के मध्यस्थता का प्रावधान करता है। पैरा 59 अधिक प्रतिबंधात्मक है और अदालत को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या मध्यस्थता समझौता

मौजूद है - न ज्यादा, न कम। अन्य निष्कर्षों के साथ पढ़ने पर, दोनों अनुच्छेदों को कानूनी अनुपात निर्धारित करने के रूप में पढ़ना उचित होगा कि अदालत को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या अंतर्निहित अनुबंध में पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों के मध्यस्थता के लिए कोई मध्यस्थता खंड शामिल है - न ज्यादा, न कम। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (सुप्रा) और बोधारा के निर्णयों का संदर्भ पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) को यह रेखांकित करना था कि 2016 के अधिनियम 3 के संशोधनों के बाद, संदर्भ चरण में, न्यायालय उन विभिन्न पहलुओं पर विचार नहीं करेगा तथा अंतिम रूप से निर्णय नहीं देगा, जिन्हें दोनों निर्णयों में रेखांकित किया गया था।

147.10. गरवारे वाल रोप्स लिमिटेड (सुप्रा) के अलावा , इस न्यायालय ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नरभेरम पावर एंड स्टील (पी) लिमिटेड (2018) 6 एससीसी 534 और हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (सुप्रा), दोनों ही तीन न्यायाधीशों के फैसलों में बीमा अनुबंधों में संदर्भ के लिए आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि दावा मध्यस्थता समझौते से परे था और इसके द्वारा कवर नहीं किया गया था। अदालत ने महसूस किया कि कानूनी स्थिति संदेह से परे थी क्योंकि मध्यस्थता खंड का दायरा वल्कन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम महाराज सिंह (1976) 1 एससीसी 943 में दिए गए कथन द्वारा पूरी तरह से

कवर किया गया था। इसी तरह, मेसर्स पीएसए मुंबई इन्वेस्टमेंट्स पीटीई लिमिटेड बनाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, (2018) 10 एससीसी 525 में, यह न्यायालय रेफरल चरण में इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि तदनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजे गए संदर्भ को रद्द कर दिया गया तथा प्रतिवादी को उचित मंच के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

147.11. यह व्याख्या, रेफरल चरण में न्यायालय और मध्यस्थों के प्राथमिक क्षेत्राधिकार के बीच विवादों का गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के अधिकार के आवंटन को उचित रूप से संतुलित करती है। प्रथम दृष्टया न्यायिक मंच के रूप में, न्यायालय, पूर्व दृष्टया आधारहीन, तुच्छ और बेईमान मुकदमों की जाँच और उन्हें खारिज करने के लिए प्रथम दृष्टया परीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। न्यायालयों का सीमित क्षेत्राधिकार, रेफरल चरण में आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र, तत्पर और कुशल निपटान सुनिश्चित करता है।

148.

153. तदनुसार, हमारा मानना है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 में 'मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व' शब्द, मध्यस्थता समझौते की वैधता के पहलू को भी शामिल करेगा, हालाँकि रेफरल चरण में न्यायालय इस निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर प्रथम दृष्टया परीक्षण लागू करेगा। विवादास्पद और विवादास्पद तथ्यों, और उचित तर्क-योग्य

मामले आदि के मामलों में, न्यायालय पक्षकारों को मध्यस्थता समझौते का पालन करने के लिए बाध्य करेगा क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास क्षेत्राधिकार और गैर-मध्यस्थता के प्रश्न सहित विवादों का निर्णय करने का प्राथमिक क्षेत्राधिकार और प्राधिकार है ।

154. “ मध्यस्थता का निर्णय कौन करता है ?” शीर्षक के अंतर्गत चर्चा को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

154.1. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत आवेदन पर निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे पर पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (सुप्रा) में लिए गए निर्णय का अनुपात, 2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधनों के बाद (23-10-2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ) और यहां तक कि 2019 के अधिनियम 33 द्वारा संशोधनों के बाद (09-08-2019 से प्रभावी), अब लागू नहीं है।

154.2. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के तहत न्यायिक समीक्षा और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का दायरा समान है, लेकिन अत्यंत सीमित और प्रतिबंधित है।

154.3. 2016 के अधिनियम 3 और 2019 के अधिनियम 33 से स्पष्ट विधायी अधिदेश, और पृथक्करणीयता एवं सक्षमता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए , सामान्य नियम और सिद्धांत यह है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण गैर -मध्यस्थता के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने और उन पर निर्णय लेने के लिए पसंदीदा प्रथम प्राधिकारी है । न्यायालय को मध्यस्थता

अधिनियम की धारा 34(2)(क) के उप-खंड (i), (ii) या (iv) या धारा 34(2)(ख) के उप-खंड (i) के अनुसार निर्णय के बाद गैर-मध्यस्थता के पहलुओं पर "दूसरी नज़र " डालने की शक्ति प्रदान की गई है।

154.4. कभी-कभार ही न्यायालय आपत्ति के रूप में धारा 8 या 11 के स्तर पर हस्तक्षेप कर सकता है जब यह स्पष्ट रूप से और पूर्व दृष्ट्या निश्चित हो कि मध्यस्थता समझौता अस्तित्वहीन, अमान्य है या विवाद मध्यस्थता-योग्य नहीं हैं, हालाँकि मध्यस्थता-योग्य न होने की प्रकृति और पहलू , कुछ हद तक, न्यायिक जाँच के स्तर और प्रकृति को निर्धारित करेंगे। प्रतिबंधित और सीमित समीक्षा का उद्देश्य पक्षों को मध्यस्थता के लिए मजबूर होने से रोकना और उनकी रक्षा करना है जब मामला स्पष्ट रूप से ' मध्यस्थता -योग्य ' न हो और अनावश्यक बातों को समाप्त करना हो। न्यायालय डिफॉल्ट रूप से मामले को तब संदर्भित करेगा जब मध्यस्थता- योग्य न होने से संबंधित तर्क स्पष्ट रूप से तर्क-योग्य हों; जब संक्षिप्त कार्यवाही में विचार अपर्याप्त और अनिर्णायक हो; जब तथ्यों पर विवाद हो; जब मध्यस्थता का विरोध करने वाला पक्ष विलंब करने की रणनीति अपनाए या मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन को बाधित करे। यह न्यायालय के लिए एक छोटा-सा परीक्षण या विस्तृत समीक्षा करने का मंच नहीं है, जिससे कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया जा सके, बल्कि यह

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता की सत्यनिष्ठा और प्रभावकारिता की पुष्टि करने और उसे कायम रखने का मंच है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एनसीसी लिमिटेड, (2023)

2 सुप्रीम कोर्ट केस 539 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के न्यायिक घोषणाओं, विशेष रूप से विद्या ड्रोलिया और अन्य (सुप्रा) के मामले में निर्णय के सर्वेक्षण के बाद, नीचे दिए अनुसार टिप्पणी की:

राजापुरा होम्स (पी) लिमिटेड (2021) 16 एससीसी 743) में इस न्यायालय के हालिया निर्णय में, जिसमें इस न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6-ए) पर विचार करने का भी अवसर मिला था और अंततः विद्या में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का उल्लेख करने और उस पर विचार करने के बाद, यह टिप्पणी की गई है। ड्रोलिया (सुप्रा) के मामले में, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मुख्यतः यह पता लगाना है कि क्या विवाद के समाधान के लिए पक्षों के बीच कोई लिखित समझौता हुआ था और क्या पीड़ित पक्ष ने प्रथम दृष्टया तर्क-योग्य मामला प्रस्तुत किया है। यह भी कहा गया है कि सीमित अधिकार क्षेत्र, तथापि, न्यायालय को मध्यस्थता खंड के मात्र अस्तित्व से परे जाकर निरर्थक विचार करने के उसके न्यायिक कार्य से वंचित नहीं करता। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने विद्या के मामले में की गई टिप्पणियों पर

ध्यान दिया था। ड्रोलिया (सुप्रा) में कहा गया है कि सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी को रोकने के उद्देश्य से, न्यायालय किसी भी तुच्छ या परेशान करने वाले दावों को हटाने के लिए संदर्भ के चरण में 'प्रथम दृष्टया समीक्षा' कर सकता है।

12. एनटीपीसी लिमिटेड बनाम एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड, (2023) 9 सुप्रीम कोर्ट केस 385 के मामले में एक अन्य निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाद की गैर- मध्यस्थता के संबंध में कानूनी स्थिति पर विचार किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे इस प्रकार समझाया:-

कानून की स्थिति

16. वर्तमान मामले में, हम अधिनियम की धारा 11 के तहत उच्च न्यायालय के पूर्व-संदर्भ क्षेत्राधिकार से चिंतित हैं और उस सीमित दायरे को रेखांकित करना चाहेंगे जिसके भीतर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत आवेदन पर विचार किया जाना है।

17. पूर्व-रेफरल क्षेत्राधिकार के संबंध में कानून की स्थिति, जैसा कि अधिनियम में धारा 11(6-ए) के आगमन से पहले मौजूद थी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोगरा में इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए एक अच्छी तरह से व्यक्त सिद्धांत पर आधारित थी। पॉलीफैब (पी) लिमिटेड (2009) 1

एससीसी 267. बोगरा में पॉलीफैब मामले में , इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी विवाद की गैर- मध्यस्थता के मुद्दे की जाँच न्यायालय को उन मामलों में करनी होगी जहाँ अनुबंध के समझौते और निर्वहन का आरोप लगाया गया हो। बोधारा मामले के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए पॉलीफैब मामले में, इस न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी (2011) 12 एससीसी 349 में यह टिप्पणी की थी कि जब किसी डिस्चार्ज वाउचर, नो-क्लेम सर्टिफिकेट या किसी सेटलमेंट एग्रीमेंट की वैधता पर विवाद हो, तो न्यायालय को पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजने से पहले आरोपों की विश्वसनीयता की प्रथम दृष्टया जाँच करनी चाहिए। न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड बनाम जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2015) 2 एससीसी 424 मामले में भी, इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव के आरोपों की प्रथम दृष्टया आरोप लगाने वाले पक्ष द्वारा साक्ष्य के माध्यम से पुष्टि की जानी चाहिए।

18. इन उदाहरणों के विधायी प्रत्युत्तर में, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 के माध्यम से, अधिनियम की धारा 11 में उप-धारा (6-ए) जोड़ी गई, जो इस प्रकार है:

11. (6-ए) उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय, उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, किसी भी न्यायालय के किसी भी

निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित रहेगा। (जोर दिया गया)

19. विधायी परिवर्तन का संज्ञान लेते हुए, इस न्यायालय ने इयूरो में फेलगुएरा , एसए बनाम गंगावरम पोर्ट लिमिटेड, (2017) 9 एससीसी 729 ने उल्लेख किया कि 2015 के संशोधनों के बाद, अधिनियम की धारा 11(6) के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इस बात की जांच करने तक सीमित है कि क्या पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता मौजूद है - "न कुछ ज्यादा, न कुछ कम"

20. हालाँकि, वर्ष 2019 में, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एंटीक आर्ट एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड (2019) 5 एससीसी 362 में, इस न्यायालय ने मध्यस्थता के संदर्भ के लिए एक आवेदन के विरोध में "समझौते और संतुष्टि" की आपत्ति को स्वीकार कर लिया था।

21. इस न्यायालय को एंटीक आर्ट एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड (सुप्रा) में दृष्टिकोण को उलटने में ज्यादा समय नहीं लगा। मायावती ट्रेडिंग (पी) लिमिटेड बनाम प्रद्युत देब बर्मन (2019) 8 एससीसी 714 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एंटीक आर्ट एक्सपोर्ट्स में उपर्युक्त निर्णय को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि: (मायावती ट्रेडिंग केस, एससीसी पीपी. 724-25, पैरा-10)

“10. यह स्थिति होने के नाते, यह स्पष्ट है कि 2015 के संशोधन से पहले का कानून जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें यह शामिल होगा कि क्या समझौता और संतुष्टि हुई है, अब विधायी रूप से खारिज कर दिया गया है। यह स्थिति होने के नाते, उपरोक्त निर्णय में निहित तर्क से सहमत होना मुश्किल है, क्योंकि धारा 11(6-ए) एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित है और इसे संकीर्ण अर्थ में समझा जाना चाहिए जैसा कि इयूरो के फैसले में निर्धारित किया गया है । फेलगुएरा , एस.ए.”

(मूल में जोर दिया गया है)

विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और प्रथम दृष्टया परीक्षण के सामान्य सूत्र के माध्यम से नेविगेट करने के बाद, इसे आधिकारिक रूप से नीचे माना गया था: -

विद्या में बताए गए सामान्य नियम और सिद्धांत का पालन करना ड्रोलिया (सुप्रा) में यह न्यायालय लगातार यह मानता रहा है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने और उन पर निर्णय लेने के लिए प्रथम वरीयता प्राप्त प्राधिकारी है । प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम गैलेक्सी इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग (प्रा.) लिमिटेड (2021) 5 एससीसी 671, संजीव प्रकाश बनाम सीमा कुकरेजा (2021) 9 एससीसी 732 और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

लिमिटेड बनाम एनसीसी लिमिटेड (2023) 2 एससीसी 539 में, पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था, क्योंकि इनमें से प्रत्येक मामले में गैर- मध्यस्थता की आपत्ति पर प्रथम दृष्टया समीक्षा अनिर्णायक पाई गई थी। सामान्य सिद्धांत के अपवाद के बाद कि न्यायालय पक्षों को मध्यस्थता के लिए नहीं भेज सकता है जब यह स्पष्ट हो कि मामला स्पष्ट रूप से और पूर्व दृष्टया गैर- मध्यस्थता योग्य है , बीएसएनएल बनाम नॉर्टेल नेटवर्क्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड (2021) 5 एससीसी 738 (इसके बाद "नॉर्टेल नेटवर्क्स") और सिकंदराबाद छावनी बोर्ड बनाम बी. रामचंद्रैया एंड संस (2021) 5 एससीसी 705 में, मध्यस्थता से इनकार कर दिया गया क्योंकि पक्षों के दावे स्पष्ट रूप से समय-बाधित थे।

सुई की आँख

25. उपर्युक्त उदाहरण विधि की इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम की धारा 11(6) के अंतर्गत न्यायालयों का रेफरल-पूर्व क्षेत्राधिकार अत्यंत संकीर्ण है और इसमें दो प्रकार की जाँचें शामिल हैं। प्राथमिक जाँच मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के बारे में है, जिसमें समझौते के पक्षकारों और आवेदक की उक्त समझौते से निजता के बारे में भी जाँच शामिल है। ये ऐसे मामले हैं जिनकी रेफरल न्यायालय द्वारा गहन जाँच आवश्यक है। रेफरेंस चरण में ही जो द्वितीयक जाँच हो सकती है, वह विवाद की गैर-मध्यस्थता के संबंध में है ।

26. एक सामान्य नियम और सिद्धांत के रूप में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण गैर- मध्यस्थता के सभी प्रश्नों का निर्धारण और निर्णय करने के लिए प्रथम वरीयता प्राप्त प्राधिकारी है । नियम के अपवाद के रूप में, और कभी-कभार आपत्ति के रूप में, रेफरल न्यायालय उन दावों को अस्वीकार कर सकता है जो स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्षतः मध्यस्थता योग्य नहीं हैं। इस स्थिति की व्याख्या, विद्या में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर की गई है। ड्रोलिया एवं अन्य (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय ने नॉर्टेल नेटवर्क्स (सुप्रा) में एक बाद के फैसले में कहा: (नॉर्टेल नेटवर्क्स मामला, एससीसी पृष्ठ 764, पैरा 45)

"45. ..45.1. ... न्यायिक मंच के रूप में धारा 11 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, न्यायालय प्रथम दृष्टया योग्यताहीन, तुच्छ और बेईमान मुकदमे की जांच और उसे खारिज करने के लिए प्रथम दृष्टया परीक्षण का प्रयोग कर सकता है। न्यायालयों का सीमित अधिकार क्षेत्र रेफरल चरण में शीघ्र और कुशल निपटान सुनिश्चित करेगा। रेफरल चरण में, न्यायालय "केवल" तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब यह "स्पष्ट" हो कि दावे पूर्व दृष्टया समय-बाधित और मृत हैं, या कोई विवाद विद्यमान नहीं है।"

27. मध्यस्थता न होने की जाँच के लिए जाँच का मानक केवल प्रथम दृष्टया ही है। रेफरल अदालतों को विवादित तथ्यों की पूरी समीक्षा नहीं करनी चाहिए; उन्हें केवल प्राथमिक समीक्षा तक ही सीमित रहना चाहिए और तथ्यों को स्वयं

बोलने देना चाहिए। इसके लिए अदालतों को यह भी जाँचना आवश्यक है कि मध्यस्थता का दावा वास्तविक है या नहीं। तथ्यों की प्रथम दृष्टया जाँच से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलना चाहिए कि इस बात में लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि दावा मध्यस्थता योग्य नहीं है। दूसरी ओर, यदि थोड़ा सा भी संदेह हो, तो नियम यह है कि विवाद को मध्यस्थता के लिए रेफर कर दिया जाए।

13. मैजिक आई डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स ग्रीन एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य, (2023) 8 सुप्रीम कोर्ट केस 50 के मामले में एक और हालिया न्यायिक घोषणा में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की गई :-

“8. उपरोक्त मुद्दे पर विचार करते समय, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6-ए) जिसे मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम, 2015 के माध्यम से जोड़ा गया है, को पढ़ा जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:

“11. (6-ए) सर्वोच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय, उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय, किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित रहेगा” (जोर दिया गया)

9. इस प्रकार, मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद, अधिनियम की धारा 11(6) के अंतर्गत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल इस बात की जाँच तक सीमित है कि क्या पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद है - "न ज्यादा, न कम"। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 11(6-ए) के अनुसार, रेफरल न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के संबंध में विवाद/ मुद्दे पर विचार करे।

10. इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6) के अंतर्गत न्यायालय का रेफरल-पूर्व क्षेत्राधिकार बहुत संकीर्ण है और इसमें दो प्रकार की जाँचें शामिल हैं। प्राथमिक जाँच मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता के बारे में होती है, जिसमें समझौते के पक्षकारों और आवेदक की उक्त समझौते से निजता के बारे में भी जाँच शामिल होती है। उक्त मामले में रेफरल न्यायालय द्वारा गहन जाँच की आवश्यकता है। (एनटीपीसी मामले में निर्णय का पैरा 25)। रेफरेंस चरण में ही जो द्वितीयक जाँच हो सकती है, वह विवाद की गैर- मध्यस्थता के संबंध में है। दोनों अलग और विशिष्ट हैं।

14. गैर-मध्यस्थता और रेफरल चरण में न्यायिक समीक्षा के दायरे के संबंध में उपरोक्त स्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने

वाले आवेदन पर विचार करते हुए, मैं अब वर्तमान आवेदन में उठाए गए मुद्दों पर विचार करूंगा।

15. पक्षकारों की दलीलों से यह स्वीकृत स्थिति प्रकट होती है कि मेसर्स वर्मा एंड कंपनी 1932 के अधिनियम के तहत एक पंजीकृत फर्म थी और दो भागीदारों में से एक, दिनेश कुमार वर्मा, उनके पुत्र अक्षय की मृत्यु के बाद, वर्मा (यहां आवेदक) को 24.12.2013 से साझेदार के रूप में स्वीकार किया गया और नई साझेदारी का गठन किया गया जो सीता देवी के बीच 24.12.2013 को निष्पादित साझेदारी विलेख के माध्यम से अस्तित्व में आई। वर्मा और अक्षय वर्मा द्वारा हस्ताक्षरित, जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि साझेदारी विलेख के खंड-9 में यह प्रावधान है कि सभी विवादों का निपटारा 1996 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। साझेदारी विलेख का खंड-9 इस प्रकार है:-

“9. सभी विवादों का निपटारा भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा।”

16. सीता देवी वर्मा द्वारा 14.03.2022 को बैंक को पत्र लिखकर फर्म के नाम से खाते बंद करने का अनुरोध करने पर विवाद उत्पन्न हो गया। जब बैंक ने दूसरे भागीदार अक्षय को सूचित किया, वर्मा फर्म के खातों को फ्रीज

करने के सीता देवी वर्मा के अनुरोध के संबंध में, दूसरे भागीदार ने बैंक से अनुरोध पर आगे कार्रवाई न करने का अनुरोध किया। आवेदक का यह भी कहना है कि बाद में सीता देवी वर्मा ने 21.04.2022 को बैंक के शाखा प्रबंधक को एक पत्र भेजकर फर्म के ओवरड्राफ्ट खाते को पुनः आरंभ करने का अनुरोध किया, जिसके बाद आवेदक अक्षय का एक पत्र भी भेजा गया। वर्मा को सूचित किया गया कि दोनों पक्षों के बीच गलतफहमी दूर हो गई है। इस बीच, सीता देवी वर्मा का 12.07.2022 को निधन हो गया। हालाँकि, बैंक ने 04.08.2022 को मेसर्स वर्मा एंड कंपनी, अक्षय को एक कानूनी नोटिस भेजा। वर्मा , मृतक सीता देवी वर्मा के कानूनी प्रतिनिधि और मृतक राजेंद्र के कानूनी प्रतिनिधि वर्मा को फर्म का पुनर्गठन करके बैंक के पक्ष में आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करने या ब्याज और अन्य खर्चों के साथ 1,75,33,186 /- रुपये की बकाया राशि चुकाने के लिए कहा गया है, अन्यथा उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

17. इसलिए, एक कानूनी मुद्दा जो विचारणीय है वह यह है कि क्या फर्म केवल दो साझेदारों के होते हुए और एक साझेदार की मृत्यु हो जाने के बावजूद विघटित हो गई थी।

इस संबंध में कानूनी स्थिति की जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद लाईकीद्दीन एवं अन्य बनाम कमला देवी मिश्रा (मृत) द्वारा

एल.आर. एवं अन्य (2010) 2 सर्वोच्च न्यायालय मामले 407 के मामले में की थी। विचारणीय मुद्दों में से एक यह था कि क्या साझेदारी फर्म, 1932 के अधिनियम की धारा 42(सी) के आधार पर, एक साझेदार की मृत्यु के कारण विघटित हो गई थी, ऐसे तथ्यों पर, जहां साझेदारी में केवल दो साझेदार थे और उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी।

18. 1932 के अधिनियम की धारा 42 में निहित प्रावधानों के आलोक में तथा साझेदारी विलेख में किसी भी साझेदार की मृत्यु के बावजूद उसे जीवित रखने का प्रावधान होने के बावजूद, विधिक स्थिति की जांच निम्नानुसार की गई:-

“22. इस अपील में प्रतिवादियों द्वारा उठाया गया एकमात्र मुद्दा, जो कि अपील संख्या 4411-12/2002 में अपीलकर्ता हैं, यह है कि क्या निचली अदालतों का यह निष्कर्ष कि साझेदारी फर्म एक साझेदार की मृत्यु के कारण विघटित हो गई थी, साझेदारी अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों अर्थात् उसी की धारा 42 (सी) के प्रकाश में सही था।

23. इससे पहले कि हम निचली अदालतों द्वारा निकाले गए इस समवर्ती निष्कर्ष की सत्यता की जाँच करें, भागीदारी अधिनियम, 1923 के प्रासंगिक प्रावधानों और मूल वादी और मूल प्रतिवादी के बीच हुए साझेदारी विलेख के प्रासंगिक खंडों

की जाँच करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 4 के तहत "साझेदारी" की परिभाषा इस प्रकार है:

"4. 'साझेदारी', 'साझेदार', 'फर्म' और 'फर्म का नाम' की परिभाषा।- " साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभ को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसे सभी या उनमें से कोई एक सभी के लिए कार्य करते हुए चला रहा है।"

24. अधिनियम की धारा 42 इस प्रकार है:

"42. कुछ आकस्मिकताओं के घटित होने पर विघटन :- भागीदारों के बीच अनुबंध के अधीन रहते हुए, एक फर्म विघटित हो जाती है-

(क) यदि एक निश्चित अवधि के लिए गठित की गई है, तो अवधि की समाप्ति पर;

(ख) यदि एक या अधिक साहसिक कार्यों या उपक्रमों को पूरा करने के लिए गठित की गई है, तो उसके पूरा होने पर;

(ग) एक भागीदार की मृत्यु पर; और

(घ) एक भागीदार के दिवालिया घोषित होने पर।" (जोर दिया गया)

25. किसी एक साझेदार की मृत्यु के कारण साझेदारी फर्म का विघटन पक्षों द्वारा किए गए अनुबंध के अधीन है। इस संदर्भ में, साझेदारी विलेख की शर्तों का उल्लेख करना उचित है। साझेदारी विलेख का खंड 22 इस प्रकार है:

“साझेदारी इस तिथि से निश्चित 42 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी और किसी भी साझेदार की मृत्यु का फर्म के विघटन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

इस खंड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी साझेदार की मृत्यु का फर्म के विघटन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम साझेदारी विलेख के इस खंड को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने की स्थिति में नहीं हैं।

26. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूँकि पक्षकार इस बात पर सहमत हुए थे कि किसी भी साझेदार की मृत्यु के बावजूद, मूल वादी (अब दिवंगत) की मृत्यु के बावजूद, फर्म 42 वर्षों तक चलती रहेगी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि जिस साझेदार की मृत्यु हो जाती है, उसके कानूनी प्रतिनिधि पर साझेदारी का एक नया विलेख करने का दायित्व होगा। यदि वे नया साझेदारी समझौता करने से इनकार करते हैं, तो कानूनी प्रतिनिधियों को लाभों का दावा करने से रोक दिया जाएगा।

27. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि साझेदारी फर्म एक साझेदार की मृत्यु के कारण भंग हो गई है, उच्च न्यायालय ने सही ढंग से श्रीमती पर भरोसा किया था। एस. पर्वतम्मल बनाम सीआईटी (1987) 163 आईटीआर 161 (मैसड.), जिसमें इस न्यायालय ने माना कि दो भागीदारों वाली फर्म में, एक भागीदार की मृत्यु के कारण फर्म स्वतः ही विघटित हो

जाती है और इस प्रकार टिप्पणी की गई: (आईटीआर पृ.161-62)

“.... एक साझेदारी सामान्यतः भागीदार की मृत्यु पर विघटित हो जाती है जब तक कि मूल साझेदारी विलेख में कोई समझौता न हो। यह मानते हुए भी कि दो भागीदारों वाली साझेदारी में ऐसा कोई समझौता था, उनमें से एक की मृत्यु पर साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है और ऐसी कोई साझेदारी नहीं बचती है जो बची हो और जिसमें किसी तीसरे पक्ष को शामिल किया जा सके। इसलिए एस की मृत्यु पर मूल साझेदारी विघटित हो गई। बाद में करदाता को भागीदार के रूप में लेना केवल आर और करदाता के बीच एक नई साझेदारी में प्रवेश करने के परिणामस्वरूप था । साझेदारी वंशानुगत स्थिति का मामला नहीं था बल्कि पूरी तरह से अनुबंध का मामला था।”

उपर्युक्त मामले के आलोक में, यह स्पष्ट है कि जब साझेदारी फर्म में केवल दो साझेदार होते हैं, तो उनमें से एक की मृत्यु होने पर, फर्म को विघटित मान लिया जाता है, भले ही ऐसा कोई खंड मौजूद हो जो अन्यथा कहता हो। साझेदारी साझेदारों के बीच एक अनुबंध है। दूसरे साझेदार की स्वीकृति के बिना कोई भी अनुबंध एकतरफा नहीं हो सकता।

28. अपीलकर्ता, मूल वादी (अब दिवंगत) के कानूनी प्रतिनिधि फर्म को जारी रखने या नई फर्म बनाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते थे और उन्हें साझेदारी जारी रखने के लिए नहीं

कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है क्योंकि साझेदारी वंशानुगत स्थिति का मामला नहीं है बल्कि पूरी तरह से अनुबंध का मामला है, जो धारा 4 के तहत साझेदारी की परिभाषा से भी स्पष्ट है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट का यह मानना उचित था कि फर्म भागीदारों में से एक की मृत्यु के कारण भंग हो गई और प्रथम अपीलीय अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखने में सही दृष्टिकोण अपनाया है।

19. उपर्युक्त निर्णय के मद्देनजर, कानूनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों भागीदारों के बीच साझेदारी विलेख में किसी भी खंड के बावजूद, भागीदारों में से किसी एक की मृत्यु के बाद भी साझेदारी को जीवित रखने के लिए, भागीदारों में से किसी एक की मृत्यु पर, साझेदारी कानून के संचालन से भंग हो जाती है।

20. हालांकि, निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि क्या फर्म के विघटन के बावजूद, साझेदारी विलेख में निहित मध्यस्थता खंड अभी भी जीवित रहेगा और 1996 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मृतक भागीदार के कानूनी प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कानूनी स्थिति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रवि प्रकाश गोयल बनाम चंद्र प्रकाश गोयल और अन्य, (2008) 13 सुप्रीम कोर्ट के मामले 667 के मामले में पूरी तरह

से समझाया गया है । विचार और उत्तर के लिए जो मुद्दे उठे, वे इस प्रकार थे: -

“16. उपरोक्त दलीलों पर, हमारे विचार के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न उभरते हैं:

(क) जहां खातों के प्रतिपादन के लिए मुकदमा करने का अधिकार मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि पर बना रहता है, क्या कानूनी प्रतिनिधि साझेदारी विलेख में निहित मध्यस्थता खंड को लागू करने के हकदार नहीं हैं?

(ख) क्या साझेदार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों द्वारा मध्यस्थता शुरू की जा सकती है, विशेष रूप से जहां विवाद साझेदार के जीवनकाल के दौरान ही उत्पन्न हो गया था?

(ग) क्या भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 48 के साथ धारा 46 तथा मध्यस्थता अधिनियम, 1999 की धारा 40 के मद्देनजर, याचिकाकर्ता भागीदारी विलेख के मध्यस्थता खंड के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति का दावा करने का हकदार है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इन प्रावधानों की अनदेखी करके गलती की है?

1932 के अधिनियम और 1996 के अधिनियम दोनों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में कानूनी स्थिति की जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी, जो इस प्रकार है:-

"17. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 40 और भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 46, 47 और 48 को पुनः उद्धृत करना उपयोगी होगा: 40. मध्यस्थता करार, पक्षकार की मृत्यु के कारण समाप्त नहीं होगा। (1) कोई मध्यस्थता समझौता किसी भी पक्षकार की मृत्यु के कारण न तो मृतक के संबंध में और न ही किसी अन्य पक्षकार के संबंध में समाप्त होगा, बल्कि ऐसी स्थिति में मृतक के विधिक प्रतिनिधि द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा।

(2) मध्यस्थ का अधिदेश किसी ऐसे पक्षकार की मृत्यु से समाप्त नहीं होगा जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था।

(3) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसके आधार पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर कार्यवाही का कोई अधिकार समाप्त हो जाता है।"

* * * *

"46. विघटन के पश्चात् व्यवसाय का समापन करने का साझेदारों का अधिकार।- किसी फर्म के विघटन पर, प्रत्येक साझेदार या उसका प्रतिनिधि, अन्य सभी साझेदारों या उनके प्रतिनिधियों के विपरीत, फर्म की संपत्ति को फर्म के ऋणों और दायित्वों के भुगतान में लगाने और अधिशेष को साझेदारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच उनके अधिकारों के अनुसार वितरित करने का हकदार है।

47. समापन के प्रयोजनों के लिए साझेदारों का निरंतर अधिकार।- किसी फर्म के विघटन के पश्चात्, फर्म को बाध्य करने का प्रत्येक साझेदार का अधिकार, और साझेदारों के अन्य पारस्परिक अधिकार और दायित्व, विघटन के बावजूद, फर्म के मामलों का समापन करने और विघटन के समय शुरू हुए परंतु अधूरे लेन-देन को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, परंतु अन्यथा नहीं:

बशर्ते कि फर्म किसी भी स्थिति में उस साझेदार के कार्यों से आबद्ध न हो जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो; परंतु यह परंतुक किसी ऐसे व्यक्ति के दायित्व को प्रभावित नहीं करता है जिसने निर्णय के पश्चात् स्वयं को दिवालिया के साझेदार के रूप में प्रस्तुत किया हो या जानबूझकर स्वयं को दिवालिया के साझेदार के रूप में प्रस्तुत होने दिया हो।

48. साझेदारों के बीच खातों के निपटान की पद्धति.- विघटन के पश्चात् फर्म के खातों के निपटान में, साझेदारों की सहमति के अधीन, निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाएगा:-

(क) पूंजी की कमियों सहित हानियों का भुगतान पहले लाभ से, फिर पूंजी से, और अंत में, यदि आवश्यक हो, तो साझेदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस अनुपात में किया जाएगा जिसमें वे लाभ साझा करने के हकदार थे;

(ख) फर्म की आस्तियां , जिनमें पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए भागीदारों द्वारा योगदान की गई

कोई राशि भी शामिल है, निम्नलिखित तरीके और क्रम में लागू की जाएंगी-

(i) तीसरे पक्ष को फर्म के ऋण का भुगतान करने में ;

(ii) प्रत्येक साझेदार को पूंजी से भिन्न अग्रिम के लिए फर्म से देय राशि का अनुपातिक रूप से भुगतान करना ;

(iii) प्रत्येक साझेदार को उसकी पूंजी के मद में देय राशि का उचित भुगतान करना; तथा

(iv) शेष राशि, यदि कोई हो, साझेदारों के बीच उस अनुपात में विभाजित की जाएगी जिसमें वे लाभ साझा करने के हकदार थे।"

18. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 40 से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता करार किसी पक्षकार की मृत्यु से समाप्त नहीं होता है और ऐसी मृत्यु पर यह मृतक के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा या उनके विरुद्ध प्रवर्तनीय होता है, न ही मध्यस्थ का प्राधिकार उसे नियुक्त करने वाले पक्षकार की मृत्यु से प्रतिसंहत होता है, जो किसी ऐसे कानून के प्रवर्तन के अधीन है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति की मृत्यु से उस व्यक्ति के कार्यवाई के अधिकार का उन्मूलन हो जाता है।

19. धारा 2(1)(जी) "कानूनी प्रतिनिधि" को परिभाषित करती है जो इस प्रकार है:

"2. (1)(जी) "कानूनी प्रतिनिधि" का अर्थ है वह व्यक्ति जो कानून में किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो मृत व्यक्ति की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है, और, जहां कोई पक्ष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, वह व्यक्ति जिस पर ऐसा कार्य करने वाले पक्ष की मृत्यु पर संपत्ति विकसित होती है;"

20. 'कानूनी प्रतिनिधि' की परिभाषा इसलिए आवश्यक हो गई क्योंकि ऐसे प्रतिनिधि मध्यस्थता समझौते से बंधे होते हैं और उसे लागू करने के हकदार भी होते हैं। धारा 40 स्पष्ट रूप से कहती है कि मध्यस्थता समझौता किसी पक्षकार की मृत्यु के कारण समाप्त नहीं होता। यह समझौता मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा या उनके विरुद्ध प्रवर्तनीय रहता है। हमारी राय में, जिस व्यक्ति को मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, वह एक कानूनी व्यक्ति (प्रतिनिधि) का दर्जा प्राप्त करता है। 1996 के अधिनियम की धारा 35, जो मध्यस्थता निर्णय को अंतिम रूप देती है, कहती है कि निर्णय का "पक्षकारों और उसके अंतर्गत दावा करने वाले व्यक्तियों" पर बाध्यकारी प्रभाव होगा। मृत व्यक्ति के अधिकारों के अंतर्गत दावा करने वाले व्यक्ति मृतक पक्षकार के निजी प्रतिनिधि होते हैं और उन्हें निर्णय को लागू करने का अधिकार होता है और वे उससे बंधे भी होते हैं। मध्यस्थता समझौता मृतक पक्षकार के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा या उसके

विरुद्ध प्रवर्तनीय होता है, बशर्ते कि वाद हेतुक के संबंध में वाद दायर करने का अधिकार बना रहे।

21. हम पहले ही भागीदारी अधिनियम की धारा 46, 47 और 48 का उद्धरण दे चुके हैं। धारा 46 दो बातें प्रदान करती है, अर्थात्, पहला व्यवसाय की परिसंपत्तियों की वसूली करना और फिर उन्हें देनदारियों के निर्वहन के लिए लागू करना और अंत में, यदि कोई अधिशेष हो, तो उसे भागीदारों के बीच वितरित करना। धारा 46 केवल इतना अधिकार देती है कि प्रत्येक भागीदार यह दावा करेगा कि ऐसा भागीदारों को उनके शेयरों के अनुसार अधिशेष के अंतिम वितरण के लिए किया जाना है। अधिशेष के वितरण से संबंधित बाद के अधिकार को लागू करने के लिए एक मुकदमे को आम तौर पर एक खाते के लिए मुकदमा कहा जाता है जिसका अर्थ है कि तदनुसार खाता लिया गया। एक भागीदार के खाते के लिए मुकदमा दायर करने का यह अधिकार इस तथ्य से प्रभावित नहीं होता है कि सेवानिवृत्त भागीदार ने पहले ही फर्म के खातों का निरीक्षण कर लिया है। हालाँकि, धारा 46 केवल अधिशेष में भागीदारों या उनके कानूनी प्रतिनिधियों के अधिकारों की घोषणा है और अधिशेष की गणना करने का तरीका निर्धारित नहीं करती है। विघटित फर्म के समापन पर साझेदार का हिस्सा केवल उस अवशेष में शामिल होता है जो धारा 48 के विभिन्न खंडों में उल्लिखित दायित्वों का भुगतान करने के बाद बचता है। साझेदारों को पूँजी और अग्रिम राशि का

भुगतान अवशेष में से नहीं होता है। अवशेष का मूल्य ज्ञात करने के लिए साझेदार को पूँजी निवेश के रूप में भुगतान की गई राशि को घटाना होगा, क्योंकि साझेदार के हिस्से का मूल्य अवशेष में उसका अनुपात ही होता है।

22. "साझेदार के प्रतिनिधि का अधिकार.- साझेदार के प्रतिनिधि का अधिकार वास्तव में वसूली पर अधिशेष परिसंपत्तियों के विरुद्ध दावा है - चाहे अधिशेष पूरी तरह से वसूली की आय से बना हो या इसमें संपत्ति की कुछ विशिष्ट वस्तुएं शामिल हों, जो साझेदार की मृत्यु पर मौजूद थीं। परिस्थितियों में साझेदार का उचित उपाय यह है कि वह अपने हिस्से का पता लगाने के लिए खाते बनवाए और यदि खातों के लिए वाद लाने का अधिकार सीमा द्वारा वर्जित है, तो साझेदार परिसंपत्तियों पर कब्जा रखने वाले किसी भी साझेदार पर उसमें हिस्सेदारी के लिए वाद नहीं कर सकता है, और सीमा सीमा अधिनियम की धारा 5 द्वारा शासित होगी।"

23. फर्म के विघटन पर मध्यस्थता खंड समाप्त नहीं होता है और इसलिए यदि मृतक साझेदार के जीवनकाल के दौरान कोई विवाद उत्पन्न हुआ था, तो उसके कानूनी प्रतिनिधि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 20 के तहत कार्यवाही करने के हकदार होंगे।

24. जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है और साझेदारी समाप्त हो जाती है, तो जीवित साझेदार का न केवल यह अधिकार है, बल्कि यह उसका कर्तव्य भी है कि वह साझेदारी

के ऋणों के भुगतान सहित साझेदारी के मामलों को समाप्त करने के उद्देश्य से परिसंपत्तियों को प्राप्त करे। हालाँकि, यह सत्य है कि सामान्य अर्थों में, मृतक साझेदार के निष्पादकों या प्रशासकों को साझेदारी में उसके हित और साझेदारी खाते के संबंध में साझेदारी परिसंपत्तियों पर ग्रहणाधिकार रखने वाला कहा जा सकता है।

25. धारा 47: यह स्पष्ट है कि विघटन के प्रारंभ होने से भागीदारों का अधिकार तुरंत समाप्त नहीं होता। ऐसा अधिकार कम से कम दो उद्देश्यों के लिए जारी रहता है, अर्थात् (1) जहाँ तक फर्म के कार्यों को समाप्त करने के लिए आवश्यक हो; और (2) उस लेन-देन को पूरा करने के लिए जो शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

26. धारा 48: यह दो मूलभूत प्रस्ताव प्रस्तुत करती है जो भागीदारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अनुरूप हैं, अर्थात् (1) हानियों के भुगतान के संबंध में; और (2) आस्तियों के उपयोग के संबंध में। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 48 के प्रावधान भागीदारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों का ही परिणाम हैं। इसलिए, दोनों धाराओं को एक साथ पढ़ा और व्याख्यायित किया जाना आवश्यक है।

27. हमारा मत है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 46 के साथ धारा 48 और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 40 के प्रावधानों के मद्देनजर, साझेदारी विलेख के मध्यस्थता खंड के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु

आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य था और विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने उक्त प्रावधानों की अनदेखी करके त्रुटि की है। हालाँकि साझेदारी फर्म के खातों के प्रतिदान हेतु वाद दायर करने का अधिकार मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि के पास बना रहता है, फिर भी वह साझेदारी विलेख में निहित मध्यस्थता खंड का आह्वान करने का भी हकदार है।

21. यद्यपि इस पहलू पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों का भी इस न्यायालय के समक्ष उल्लेख किया गया है, फिर भी रवि प्रकाश गोयल (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रामाणिक निर्णय के मद्देनजर, इस न्यायालय के विचार को अन्य प्राधिकारियों के साथ जोड़ना आवश्यक नहीं है। अतः, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि सीता देवी वर्मा की मृत्यु के बाद , ऐसा कोई मध्यस्थता समझौता विद्यमान नहीं है जिससे आवेदक विवाद के मामले में मध्यस्थ की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त कर सके, विफल हो जाता है और एतद्वारा अस्वीकार किया जाता है, विशेष रूप से तब जब प्रतिवादी द्वारा सीता देवी वर्मा की मृत्यु के अलावा समझौते के अस्तित्व और/या वैधता पर प्रश्न उठाने का कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

22. विचारणीय अगला मुद्दा यह होगा कि क्या विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं है । मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु आवेदन और मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु

नोटिस की विषय-वस्तु से पता चलता है कि सीता देवी वर्मा के जीवित रहते हुए भी, मेसर्स वर्मा एंड कंपनी फर्म के खातों के संचालन के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ था, क्योंकि सीता देवी वर्मा ने बैंक को फर्म के खाते फ्रीज करने के लिए पत्र भेजा था। हालाँकि, आवेदक के अनुसार, बाद में उन्होंने अपना अनुरोध वापस ले लिया था और खातों के संचालन के लिए सहमति दे दी थी। यह भी पता चला है कि बैंक ने फर्म और मृतक सीता देवी वर्मा के कानूनी प्रतिनिधियों को कानूनी नोटिस भी दिया है। आवेदक साझेदारी फर्म के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों पर न्यायनिर्णयन और उसके निर्धारण की मांग करता है, क्योंकि बैंक ने बैंक को दिए गए ऋण की वसूली के लिए कानूनी नोटिस भेजा है। आवेदक का दावा है कि इस संबंध में किसी समझौते के अभाव में सभी साझेदार हानि और लाभ में समान हिस्से के हकदार हैं और साझेदार फर्म द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी हैं। आवेदक के अनुसार, अधिकारों और दायित्वों से संबंधित सभी विवादों का निपटारा उचित कार्यवाही के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, इसलिए मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु कानूनी नोटिस दिया गया है। मृतका सीता देवी वर्मा की संपत्ति पर मृतका के कानूनी प्रतिनिधियों का कब्जा है।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त अनेक निर्णयों में संक्षेप में निर्धारित गैर- मध्यस्थता के परीक्षण को लागू करने और "सुई की आँख" परीक्षण को लागू करने पर, यह नहीं माना जा सकता है कि वर्तमान मामला "गैर- मध्यस्थता विवाद" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

24. वीजीपी मरीन किंगडम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम के एलेन अर्नोल्ड, (2023) 1 सुप्रीम कोर्ट केस 597 के मामले में हाल ही में दिए गए न्यायिक फैसले में , कानूनी स्थिति, जैसा कि ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है, नीचे दोहराई गई है:-

“11. विद्या के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार ड्रोलिया एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में, जब तक कि प्रथम दृष्टया यह न पाया जाए कि विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं है और यदि इस पर और गहन विचार-विमर्श की आवश्यकता है, मध्यस्थता से संबंधित विवाद मध्यस्थ पर छोड़ दिया जाना चाहिए। विद्या मामले में इस न्यायालय का निर्णय ड्रोलिया एवं अन्य (सुप्रा) तीन न्यायाधीशों की पीठ का अनुवर्ती निर्णय है, जिसमें अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत आवेदन के चरण में न्यायालय के दायरे और परिधि पर संपूर्ण कानून पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया है।”

मीनाक्षी सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड बनाम अभ्युदय ग्रीन इकोनॉमिक जोन्स प्राइवेट लिमिटेड, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1616

के मामले में एक अन्य हालिया न्यायिक फैसले में, विद्या ड्रोलिया एवं अन्य (सुप्रा) मामले में दिए गए कथन पर भरोसा करते हुए, कानूनी स्थिति की पुष्टि नीचे दी गई है:

"17. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालय रेफरल चरण में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब यह स्पष्ट हो कि दावे पूर्वदृष्टया समय-बाधित और निष्प्रभावी हैं, या कोई विवाद विद्यमान नहीं है। सीमा अवधि के मुद्दे के संदर्भ में, इसे गुण-दोष के आधार पर निर्णय हेतु मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जाना चाहिए। विवादित "अदावा प्रमाण पत्र" या नवीकरण और "समझौते और संतुष्टि" की दलील पर बचाव के मामले में भी यही स्थिति होगी।

25. कानूनी स्थिति यह है कि जब गैर मध्यस्थता से संबंधित विवाद स्पष्ट रूप से बहस योग्य होते हैं या जब तथ्यों पर विवाद होता है, तो न्यायालय 1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करते समय मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना पसंद करेगा, न केवल विद्या ड्रोलिया और अन्य (सुप्रा) में, बल्कि मोहम्मद मसरूर शेख बनाम भारत भूषण गुप्ता और अन्य, (2022) 4 सुप्रीम कोर्ट केस 156 सहित कई अन्य निर्णयों में भी आधिकारिक रूप से तय किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की गई थीं: -

“19. इस प्रकार, इस न्यायालय ने माना कि धारा 11 के तहत याचिका पर विचार करते समय, न्यायालय डिफॉल्ट रूप से मामले को संदर्भित करेगा जब गैर- मध्यस्थता से संबंधित तर्क स्पष्ट रूप से बहस योग्य हों। ऐसे मामले में, गैर- मध्यस्थता के मुद्दे को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा तय किए जाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। आक्षेपित आदेश के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि गैर-मध्यस्थता और समय बाधित होने के दावे के मुद्दों पर बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। वास्तव में, आक्षेपित आदेश के प्रभावी भाग के खंड (viii) में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने देखा है कि पक्षकारों के तर्क खुले रखे गए हैं। अपीलकर्ता द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर याचिकाएं, 25-5-2021 के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, जिसमें अपीलकर्ता सभी अनुमेय तर्क उठा सकता है।”

संजीव प्रकाश बनाम सीमा कुकरेजा एवं अन्य, (2021) 9 सुप्रीम कोर्ट केस 732 के मामले में अनुमोदन के साथ उद्धृत किए गए अनेक निर्णयों में भी इसी प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

“20. विद्या झोलिया एवं अन्य (सुप्रा) मामले में न्यायालय ने उस मामले के तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि उस मामले के तथ्यों की प्रथम दृष्टया समीक्षा के आधार पर किसी भी तरह यह निष्कर्ष निकालना असुरक्षित होगा कि

पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौता मौजूद है, और गहन विचार मध्यस्थ पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जिसे दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य की जांच करनी है और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है।

21. इसी तरह, भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (2021) 5 एससीसी 738 में, इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने विद्या को संदर्भित किया ड्रोलिया एवं अन्य (सुप्रा) और निष्कर्ष: (बीएसएनएल) (सुप्रा), एससीसी पृ. 765-66, पैरा 46-47)

"46. विद्या ड्रोलिया एवं अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, (2021) 2 एससीसी 1 में दिए गए निर्णय का परिणाम, इयूरो फेलगुएरा, एस.ए. (सुप्रा) और मायावती ट्रेडिंग (प्रा.) लिमिटेड (सुप्रा) में प्रतिपादित विधि की स्थिति की पुष्टि है, जो अभी भी लागू है। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि विद्या ड्रोलिया एवं अन्य (सुप्रा) ने शक्ति के दायरे पर संशोधन-पूर्व स्थिति को पुनर्जीवित नहीं किया है जैसा कि एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, (सुप्रा) में माना गया था।

47. केवल बहुत सीमित श्रेणी के मामलों में, जहाँ इस बात पर लेशमात्र भी संदेह न हो कि दावा पूर्व दृष्ट्या समय-सीमा पार कर चुका है, या विवाद

मध्यस्थता-योग्य नहीं है, न्यायालय संदर्भ देने से इनकार कर सकता है। हालाँकि, यदि ज़रा भी संदेह है, तो नियम यह है कि विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए, अन्यथा यह न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मूल मामले का अतिक्रमण होगा।

22. इसके विपरीत, धारा 11 के अंतर्गत न्यायालय मामले को तब संदर्भित करेगा जब मध्यस्थता-योग्य न होने से संबंधित विवाद स्पष्ट रूप से तर्क-योग्य हों, या जब तथ्यों पर विवाद हो। न्यायालय, इस स्तर पर, तथ्यों और कानून की ऐसी छोटी सुनवाई या विस्तृत समीक्षा नहीं कर सकता जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करे।

26. परिणामस्वरूप, मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु आवेदन स्वीकार किया जाना आवश्यक है और तदनुसार, उसे स्वीकार किया जाता है। माननीय न्यायमूर्ति पी.के. अग्रवाल (सेवानिवृत्त), सी-82, राम नगर, शास्त्री नगर, जयपुर को पक्षों के बीच विवाद का निपटारा करने और निर्णय पारित करने हेतु एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है। एकमात्र मध्यस्थ, अधिनियम 1996 की चौथी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का हकदार होगा।

27. रजिस्ट्री को माननीय न्यायमूर्ति पी.के. अग्रवाल (सेवानिवृत्त) को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में उनकी नियुक्ति के बारे में सूचित करने का निर्देश

दिया जाता है। पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे कानून के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ को सूचित करें।

(मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव) , सी.जे

संजय कुमावत-15

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी